

सतना

03 मई 2026  
रविवार

# दैनिक मीडिया ऑडिटर

सतना, रीवा एवं मनेन्द्रगढ़ से एक साथ प्रकाशित

## पंजाब-आप छोड़ भाजपा जॉइन करने वाले सांसद पर एफआईआर

गैर जमानती धाराएं लगाई; पुलिस  
अरेस्ट करने दिल्ली पहुंची तो पाठक  
पिछले दरवाजे से निकले



**मोहाली/लुधियाना, एजेंसी।** आप छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पंजाब से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दो FIR दर्ज हुई हैं। यह केस भ्रष्टाचार और शोषण से जुड़े हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, गैर-जमानती धाराओं में केस दर्ज हुआ है। संदीप पाठक केस दर्ज होने की खबर बाहर आने से पहले दिल्ली स्थित अपने घर से निकल गए। जब मीडिया उनसे बात करने पहुंची तो वह तेजी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस दिल्ली स्थित उनके घर पहुंच गई है और कर्मी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि पंजाब पुलिस या सरकारी प्रवक्ता की तरफ से इसको लेकर अभी कोई रिक्शन नहीं आया है।

संदीप पाठक से पहले आप सरकार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के जरिए पार्टी छोड़ने वाले दूसरे सांसद राजेंद्र गुप्ता की ट्राइब्यूनल फैक्ट्री में भी रोक कर चुकी है। डॉ. संदीप पाठक 25 अप्रैल को राधव चड्ढा और अशोक मित्तल के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। इसके अलावा राधव चड्ढा और हरभजन सिंह भज्जी की सिक्किम भी आप सरकार छोड़ चुकी है।

## बच्चे चिल्लाए-मम्मी बचाओ...पापा मत जलाओ छतरपुर में पिता ने कमरे में बंद कर लगाई आग; मां ने फोन पर चीखें सुनी, पड़ोसियों ने जान बचाई



**छतरपुर (म.प्र.), एजेंसी।** छतरपुर जिले के नौगांव के तिवारी मोहल्ले में शुक्रवार शाम करीब 5 बजे एक पिता ने अपने 8 और 5 साल के दो बेटों को किराए के कमरे में बंद कर आग लगा दी। उसी समय बच्चों की मां का फोन आया, जिसमें उसने उनकी चीखें सुनीं।

घर से धुआं उठता देख पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। आग बुझाकर दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में बच्चे और आरोपी पिता हल्के झुलस गए। दोनों बच्चों को नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां वे खतरे से बाहर हैं। पुलिस तांत्रिक के कहने पर घटना को अंजाम देने के एंगल से जांच कर रही है।

**पति को फोन किया, दूसरी तरफ बच्चों की चीखें सुनीं:** पलेरा थाना क्षेत्र निवासी राधवेंद्र तिवारी, पत्नी के मायके जाने के बाद, अपने बेटों जय (8 साल) और हर्ष मणि (5 साल) को लेकर छतरपुर रोड स्थित धर्म कांटा के पास तिवारी मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहा था।



**भोपाल/लखनऊ/शिमला/देहरादून** भीषण गर्मी झेल चुके देश के बड़े हिस्से में शनिवार को तेज हवाओं के साथ बारिश से राहत मिलेगी। देश के 9 राज्यों में आंधी-बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। इससे तापमान में 3-5 डिग्री तक की गिरावट होगी।

कश्मीर की चिनाब घाटी में लैंडस्लाइड के कारण डोडा-किश्तवाड़ रोड पूरी तरह बंद हो गई है। सड़क पर मलबा आने की वजह से 100 से ज्यादा गाड़ियां जाम में फंस गई हैं। मलबे को हटाने के लिए मशीनों और कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच रहा। उई 41.6 डिग्री के साथ राज्य का सबसे गर्म शहर है, जबकि हरदोई में न्यूनतम तापमान

## गर्मी के बीच एमपी-यूपी, बिहार समेत 9 राज्यों में आंधी-बारिश

कश्मीर में लैंडस्लाइड से डोडा-किश्तवाड़ रोड बंद; राजस्थान के बीकानेर-बाड़मेर में पारा 44 डिग्री



सबसे कम 17 डिग्री रहा। 27 अप्रैल को बांदा में पारा 47.6 डिग्री पहुंचने के बाद पिछले 5 दिन में पारा 6 डिग्री तक लुढ़क गया है।

मध्य प्रदेश में तेज गर्मी के दौर के बीच आंधी-बारिश होने के साथ ओले भी गिर रहे हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को ग्वालियर समेत 21 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 30 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। पिछले दो दिन में प्रदेश के 35 जिलों में बारिश, ओले या फिर आंधी चल चुकी है।

बिहार में भी बारिश को लेकर

अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 50 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। कैमूर में शुक्रवार को बिजली गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई।

राजस्थान में आंधी-बारिश के बीच गर्मी भी जारी है। शुक्रवार को बाड़मेर और बीकानेर में दिन का तापमान 44 डिग्री के ऊपर पहुंच गया। ज्यादातर शहरों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा। मौसम विभाग ने अगले तीन-चार दिनों के लिए 16 जिलों में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

## मई में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने मई में देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने और कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान जताया है। साथ ही अलग-अलग इलाकों में टैम्परेचर मिला-जुला रहेगा। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हीटवेव की स्थिति सामान्य से ज्यादा रहने की आशंका है। असम, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कुछ अलग-अलग स्थानों पर (7-20 सेमी.) बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना के कई इलाकों में ओलाघट्टि हुई है।

बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अलग-अलग जगहों पर आंधी-तूफान आया।

## देशभर में करोड़ों मोबाइल पर एकसाथ अलर्ट मैसेज आया

सायरन की आवाज सुनाई दी, सरकार ने  
इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग की



## देशभर में इमरजेंसी मैसेज की एकसाथ टेस्टिंग

शनिवार को देश के सभी राज्यों की राजधानियों और दिल्ली-हदरमें सभी मोबाइल फोन पर एकसाथ टेस्टिंग मैसेज भेजा गया। यह मैसेज हिंदी और अंग्रेजी के साथ सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी भेजा गया। इस मैसेज में लोगों को बताया गया कि यह केवल परीक्षण है और इस पर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है।

**सरकार ने पहले ही बताया था- मैसेज से घबराएं नहीं:** पहले ही मैसेज भेजकर लोगों से अपील की थी कि टेस्टिंग वाला मैसेज मिलने पर घबराएं नहीं। शनिवार का मैसेज केवल इमरजेंसी के हालात में चेतावनी देने वाले सिस्टम की जांच के लिए भेजा गया था।

**नई दिल्ली, एजेंसी।** देशभर में शनिवार सुबह 11:45 बजे कई मोबाइल फोन पर एकसाथ सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। स्क्रीन पर हिंदी-अंग्रेजी में एक मैसेज था। सायरन बंद हुआ तो मोबाइल पर मैसेज पढ़कर भी सुनाया गया। इससे कई लोग परेशान हुए, तो कई कम्प्यूज। हालांकि सरकार ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। यह मैसेज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी NDMA ने भेजा था, जो इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट डायल का हिस्सा है। NDMA ने इमरजेंसी में लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए 2 मई को इस सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया।

## भारत जल्द करेगा पड़ोसी देशों को इथेनॉल निर्यात, नेपाल के साथ शुरू हुई बातचीत

**नई दिल्ली, एजेंसी।** भारत अपनी ऊर्जा शक्ति का विस्तार अब दक्षिण एशियाई देशों (सांके) तक करने की तैयारी में है। ग्रैंड इथेनॉल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (जेईएमए) के अध्यक्ष सीके जैन ने बताया कि भारत, नेपाल को इथेनॉल निर्यात करने के लिए चर्चा कर रहा है। हाल में एक प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल का दौरा किया, जहां 10% इथेनॉल मिश्रण शुरू करने का सुझाव दिया गया है। जैन ने बताया कि वर्तमान में 1 जी इथेनॉल के निर्यात पर रोक है, लेकिन पड़ोसी देशों की मांग को देखते हुए सरकार इस पर विचार कर सकती है। इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उनके अनुसार वर्तमान में 20 लाख से 40,000 करोड़ रुपये की बचत हो रही है, जिसे 85 और 100 जैसे उच्च मिश्रण स्तरों पर ले जाने से 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाया जा सकता है।

फ्लेक्स-फ्यूल इंजनों पर उन्होंने कहा कि सरकार और एसआईएम के बीच बातचीत जारी है। अगले 2-3 वर्षों में ये वाहन सड़कों पर दिख सकते हैं। हालांकि, उन्होंने माना कि उपभोक्ताओं में माइलेज को लेकर भ्रम है, जबकि पर्यावरण और विदेशी मुद्रा के लाभ कहीं अधिक बड़े हैं।



## नेपाल के साथ संबंधों को सशक्त बनाने के लिए भारत प्रतिबद्ध : मिसरी

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने शुक्रवार को नेपाल के निवर्तमान राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा से विदाई मुलाकात की। राजधानी दिल्ली में हुई इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक और बहुआयामी साझेदारी को समीक्षा की गई। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की जानकारी साझा की। मंत्रालय के अनुसार विदेश सचिव मिसरी ने नेपाल के साथ भारत के समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंधों को और अधिक सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।



## बाघों के लिए क्यों छोटा पड़ने लगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व

9 साल में 9 की जान गई; एक-दूसरे के खून के प्यासे हुए बाघ-बाघिन

**सवाई माधोपुर, एजेंसी।** राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अब बाघों के लिए 'घर' छोटा पड़ने लगा है। अपनी सल्लनत (टेरिटरी) कायम करने की होड़ में बाघ एक-दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। आलम यह है कि पिछले 9 साल में आपसी भिड़ंत के कारण 9 बाघ अपनी जान गंवा चुके हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) ने भी इस बढ़ते संघर्ष पर चिंता जताई है।



**1980 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला**  
देश में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 1973 में हुई थी। इसी साल रणथंभौर राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व बना। साल 1980 में रणथंभौर टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क का दर्जा मिला।

**क्षमता से ज्यादा बाघ, कुनबा बढ़ा तो सिमट गया इलाका**

वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 2015-16 की रिपोर्ट के मुताबिक, रणथंभौर का क्षेत्रफल और ग्रासलैंड अधिकतम 45 से 55 बाघों के लिए उपयुक्त है। वर्तमान में यह 77 बाघ, बाघिन और शावक मौजूद हैं। सख्खा बढ़ने से जंगल का कोना-कोना बाघों से भर गया है, जिससे अवसर संघर्ष की घटनाएं हो रही हैं। टेरिटरी का गणित... 40 की जगह सिर्फ 22 किमी: NTCA की गाइडलाइन कहती है कि एक टाइगर को 40 से 50 वर्ग किमी का इलाका चाहिए।

## टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से झटका

# 'चुनाव आयोग को नियुक्ति के पूरे अधिकार, नए आदेश की जरूरत नहीं'

**नई दिल्ली, एजेंसी।** पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ झटका लगा है। चुनाव आयोग द्वारा वोटों की गिनती के लिए मुख्य रूप से केंद्र सरकार और पीएसयू के कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस अहम मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज टीएमसी की याचिका पर सुनवाई की। विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नया आदेश पारित करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल, चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वह अपने 13 अप्रैल के परिपत्र (सर्कुलर) का पूरी तरह से पालन करेगा।

तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक, इस सर्कुलर में मतगणना प्रक्रिया में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों की तैनाती का भी प्रावधान है। चुनाव आयोग के कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह दोहराया कि चुनौती दिए गए सर्कुलर को लागू किया जाएगा और मामले में आगे कोई अन्य आदेश देने से मना कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि चुनाव आयोग को नियुक्ति के पूरे अधिकार हैं।

**फर्क नहीं पड़ता कि अधिकारी केंद्र का है- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी:** सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि मतगणना के अधिकारी हैं या नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की तैनाती पूरी तरह से चुनाव आयोग की अपनी संतुष्टि पर निर्भर करती है, क्योंकि वहां

सभी पार्टियों के एजेंट मौजूद होंगे। क्या है पूरा मामला? यह पूरा मामला वोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि बंगाल में वोटों की गिनती के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) बनाया जाएगा। टीएमसी इस फैसले का विरोध कर रही है। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया में राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी बराबर शामिल किया जाना चाहिए। इसी आदेश को चुनौती देने के लिए टीएमसी ने अर्जी दी थी, जिस पर जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की।

## सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नियमों को लेकर क्या स्पष्ट किया?

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची ने नियमों को लेकर स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि नियमों में यह विकल्प पूरी तरह से खुला है कि कार्टिंग सुपरवाइजर और कार्टिंग असिस्टेंट केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं और राज्य सरकार के भी। कोर्ट ने कहा कि जब यह विकल्प खुला हुआ है, तो हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग का यह नॉटिफिकेशन नियमों के खिलाफ है। जस्टिस बागची ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वह कह सकता है कि दोनों अधिकारी केंद्र सरकार के ही होंगे।

**कपिल सिबल ने कोर्ट में क्या दलील दी?**  
टीएमसी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिबल ने चुनाव आयोग के सर्कुलर (परिपत्र) पर सवाल उठाए। सिबल ने कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग के सर्कुलर में स्पष्ट ऐसा स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है कि केवल केंद्रीय कर्मचारी ही होंगे। टीएमसी का तर्क है कि चुनाव आयोग का यह कदम जनबुझकर राज्य सरकार के कर्मचारियों को गिनती से दूर रखने के लिए उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की दलीलों पर क्या जवाब दिया? वकील सिबल की दलीलों पर जस्टिस बागची ने तुरंत अपना पक्ष रखा।

# डीडीए के प्रस्ताव पर दिल्ली के 48 गांव होंगे शहरीकृत, एमसीडी की मंजूरी से विकास को मिलेगी रफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली में एमसीडी ने डीडीए के प्रस्ताव पर 48 गांवों को शहरीकृत घोषित करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद से इन गांव में अब नियोजित विकास हो सकेगा। सड़क, बिजली, पानी, सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार इस निर्णय के बाद किया जा सकेगा।

डीडीए ने फरवरी में यह प्रस्ताव निगम को भेजा था। एमसीडी के अनुसार जिन 48 गांव के शहरीकरण की मंजूरी दी गई है उसमें बाहरी उत्तरी, उत्तरी, उत्तर-पूर्वी, उत्तर-पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में जहां भविष्य में व्यापक विकास योजनाएं लागू की जानी हैं। एमसीडी की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि यह निर्णय केवल नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाले विकास की दिशा में ठोस पहल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो गांव व्यवहार में शहरी स्वरूप ले चुके हैं, उन्हें औपचारिक रूप से शहरी दर्जा देना आवश्यक था, ताकि वहां विकास कार्यों



को व्यवस्थित रूप से लागू किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस मंजूरी के बाद निगम सदन में यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा। फिर अधिसूचना के लिए दिल्ली सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद इसके लागू होने से संबंधित क्षेत्रों में सड़क, सीवर, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और कूड़ा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं का अधिक प्रभावी और जवाबदेह तरीके

से सुनिश्चित किया जा सकेगा। शर्मा ने कहा उन्होंने आगे कहा कि इस निर्णय से अवैध निर्माण पर नियंत्रण मजबूत होगा, क्योंकि अब सभी निर्माण और भूमि उपयोग नगर निगम के नियमों के अंतर्गत आएंगे। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी स्पष्ट दिशा मिलेगी। गांव शहरीकृत होने के यह होते हैं लाभ : जब दिल्ली के किसी ग्रामीण

गांव को 'शहरीकृत' घोषित किया जाता है, तो वहां के निवासियों को कई कानूनी और बुनियादी लाभ मिलते हैं। इसमें मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। डीएलआर एक्ट से मुक्ति: शहरीकरण के बाद गांव पर दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम लागू नहीं रहता। इससे जमीन का उपयोग खेती के अलावा मकान या व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। लैंड पूलिंग पॉलिसी का लाभ: शहरीकृत होने के बाद जमीन लैंड पूलिंग पॉलिसी में आती है। इससे विकसित जमीन के बदले हिस्सा मिलता है और जमीन की कीमत बढ़ती है। बुनियादी ढांचे का विकास: क्षेत्र की जिम्मेदारी MCD या DDA के पास जाती है, जिससे सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट, पार्क और सफाई की सुविधाएं बेहतर होती हैं। नक्शा पास कराने की सुविधा: घर या दुकान बनाने के लिए लेआउट प्लान को आधिकारिक मंजूरी मिलती है, जिससे निर्माण कानूनी रूप से वैध होता है। संपत्ति की कीमत में वृद्धि:

शहरीकरण से जमीन और संपत्ति के दाम तेजी से बढ़ते हैं, साथ ही बैंक से लोन लेना आसान होता है।

व्यावसायिक अवसर: नए बाजार, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खुलने से रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ते हैं।

ये हैं वह गांव जो होंगे शहरीकृत : उत्तरी दिल्ली : पल्ला, सिंघोला, बाकोली, हमीदपुर, ताजपुर कलां, कादीपुर, मुंगेशपुर, निजामपुर, औचंदी, शाहपुर गढ़ी, रसीदपुर, ततेसर। पश्चिमी दिल्ली : झटीकरा, कंगनहेरी, दालतपुर, राजपुर कलां, घुमनहेड़ा, रावता, बंसा, खेरा, ईसापुर, बाकरगढ़, गालिबपुर, मुंडेला कलां, मुंडेला खुर्द, सुरखपुर। दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली : छावला, बिंदापुर, डाबरी, अमालतपुर खवाद, रेवला खानपुर, जफराबाद, बडूसराय, दाराला, राघवपुर, शिकारपुर, नानकहेड़ी। अन्य क्षेत्र: सभापुर, जगतपुर, बदरपुर खादर, खानपुर खानल, चिल्ला।

## गाजियाबाद में बना नया रिकॉर्ड, 1,889 करोड़ की शराब गटक गए लोग सरकार का भर गया खजाना



गाजियाबाद, एजेंसी। गाजियाबाद जिले में शराब और बीयर की खपत बढ़ रही है। यही वजह है कि शराब की बिक्री का रिकॉर्ड टूटा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आबकारी विभाग को पहली बार 1,889 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री की गई है, जो कि लक्ष्य के सापेक्ष 88 प्रतिशत है। इसके अलावा जिले में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए जिले में 1,189 मामले वित्तीय वर्ष 2025-26 में दर्ज किए गए हैं, जिसमें 53 लोगों को गिरफ्तारी की गई है और 52 आरोपियों को जेल भेजा गया है। अवैध शराब की बिक्री के मामले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिले में 252 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 466 पहुंच गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 212, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 116 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

## एक बड़ी ताकत एगिजट पोल में टीवीके के नतीजों ने डीएमके के सहयोगी को भी चौंकाया

तमिलनाडु, एजेंसी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के एगिजट पोल के नतीजों में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके को भारी बढ़त दिखाई गई है। ऐसे में सत्ताधारी डीएमके के सहयोगी और एमडीएमके प्रमुख वाइको ने विजय की पार्टी की तारीफ की है और उसे एक बड़ी ताकत बताया। उन्होंने विजय की आम लोगों के बीच लोकप्रियता का हवाला देते हुए कहा, 'टीवीके एक बड़ी ताकत है और यह चौंका देने वाले नतीजे दे सकती है।' जहां ज्यादातर एगिजट पोल ने यह अनुमान लगाया है कि विजय की पार्टी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में काफी सपोर्ट जीतेगी और शायद 'किंगमेकर' बन सकती है।



वहीं, >दृष्टा स्व दृष्टस्वदृष्ट के अनुमान के अनुसार, यह नई पार्टी 234 में से 98-120 सीटें जीतकर डीएमके को चौंका सकती है। वाइको ने यह भी भविष्यवाणी की कि द्रविड़ आंदोलन तमिलनाडु की राजनीति में एक स्थायी शक्ति बना रहेगा।

तमिलनाडु और भारत के अन्य हिस्सों में विजय के चाहने वालों की एक बहुत बड़ी जमात है। उन्होंने अपने अभिनय करियर और लोकप्रियता के शिखर पर रहते हुए राजनीति में कदम रखा है। युवाओं और महिलाओं के बीच उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है। इन कारणों के उनके पक्ष में काम करने की संभावना है। हालांकि, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शिवाजी गणेशन, विजयकांत और कमल हासन सहित कई अभिनेताओं ने अपनी किस्मत आजमाई है, लेकिन वे असफल रहे। यहां तक कि सुपरस्टार रजनीकांत ने भी राजनीति से किनारा कर लिया। टीवीके ने राज्य की सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ा है। पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार का केंद्र युवाओं पर केंद्रित वादों को बनाया है, जिनमें छात्रों को बजीफा, बिना किसी गारंटी के स्टार्टअप लोन और नशामुक्त राज्य बनाने का वादा शामिल है।

## जर्मनी से 5000 सैनिक क्यों हटा रहा अमेरिका: नाटो देशों में बढ़ी चिंता, ट्रंप ने यूरोप को दे दिए ये बड़े संकेत

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने जर्मनी से करीब 5,000 सैनिक हटाने का बड़ा फैसला लिया है। यह कदम आले 6 से 12 महीनों में पूरा किया जाएगा। पेंटागन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह फैसला यूरोप में सैन्य जरूरतों और हालात की समीक्षा के बाद लिया गया है। हालांकि इस फैसले के पीछे केवल सैन्य रणनीति ही नहीं, बल्कि राजनीति और अंतरराष्ट्रीय तनाव भी बड़ा कारण माने जा रहे हैं। खासकर इराकल और ईरान युद्ध के बीच अमेरिका और जर्मनी के रिश्तों में आई खटास ने इस फैसले को और अहम बना दिया है।

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला: अमेरिका के रक्षा विभाग ने कहा कि यूरोप में अपनी सैन्य स्थिति को समीक्षा के बाद यह

निर्णय लिया गया। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिका की इरान नीति की आलोचना की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी जर्मनी से सैनिक हटाने की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप का मानना है कि नाटो देश अमेरिका का पूरा साथ नहीं दे रहे हैं। इराकल-ईरान युद्ध के बाद अमेरिका अपनी रणनीति बदल रहा है। कितनी बड़ी है जर्मनी में अमेरिकी सेना की मौजूदगी? जर्मनी में अभी करीब 36,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इनमें से लगभग 14 प्रतिशत सैनिक अब हटाए जाएंगे। जर्मनी में अमेरिका के बड़े सैन्य ठिकाने हैं जैसे रामस्टीन एयर बेस। यूरोप हम एफ्रीका कमांड का मुख्यालय भी जर्मनी में ही है। जर्मनी में अमेरिका का सबसे बड़ा विदेशी अस्पताल भी मौजूद है। इस फैसले के क्या होंगे

वैश्विक असर: माना जा रहा है कि यह कदम अमेरिका की वैश्विक ताकत दिखाने की रणनीति का हिस्सा है। इससे यूरोप को अपनी सुरक्षा खुद संभालने का संकेत मिल रहा है। नाटो देशों में पहले से ही इस फैसले को लेकर चिंता थी। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप में सुरक्षा का मुद्दा और गंभीर हो गया है। अमेरिका धीरे-धीरे अपनी जिम्मेदारी कम करने की दिशा में बढ़ रहा है। आगे क्या हो सकता है और क्यों बढ़ी चिंता: ट्रंप पहले भी अपने पहले कार्यकाल में ऐसा कदम उठाने की कोशिश कर चुके थे। उस समय यह योजना लागू हम देखेंगे कि क्या होना है। अब फिर से यह फैसला लागू होने जा रहा है, जिससे नाटो में तनाव बढ़ सकता है।

## सैन्य कार्टवाई या समझौता: ट्रंप बोले- ईरान के सामने बस दो ही रास्ते

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच तेहरान को दो ट्रंक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सामने स्पष्ट विकल्प हैं - या तो बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जाए या फिर सैन्य रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंट्रोकॉम) के कमांडर एडमिरल ब्रेड कूपर द्वारा दी गई ब्रीफिंग के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, 'विकल्प मौजूद हैं। क्या हम जमकर उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देना चाहते हैं और हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं या हम एक समझौता करने की कोशिश करना चाहते हैं। ये विकल्प हैं।' मैं ऐसा नहीं करना चाहता : ट्रंप: डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा,

'मानवीय दृष्टिकोण से मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन यह विकल्प है: क्या हम भारी बला प्रयोग करके उन्हें खत्म कर देना चाहते हैं या हम कुछ और करना चाहते हैं।' ईरान के नए प्रस्ताव पर ट्रंप असहमत: राष्ट्रपति ट्रंप ने चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से ईरान के नए प्रस्ताव पर असंतोष जताया। उन्होंने इस बात पर भी संदेह जताया है कि क्या कोई अंतिम समझौता हो सकता है। व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'वे एक सौदा करना चाहते हैं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए हम देखेंगे कि क्या होता है।' उन्होंने प्रस्ताव के उन विशिष्ट पहलुओं पर विस्तार से नहीं बताया जो उन्हें अस्वीकार्य लगे, लेकिन तेहरान की अंततः एक

समझौते पर सहमत होने की इच्छाशक्ति पर अनिश्चितता जताई। ईरानी नेतृत्व में फूट का किया दावा: व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में बोलते हुए ट्रंप ने कहा, 'उन्होंने (ईरान) प्रगति की है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे कभी वहां पहुंचेंगे।' अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के नेतृत्व के भीतर आंतरिक फूट की ओर भी इशारा किया, जिससे पता चलता है कि यह असहमति बातचीत की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा, 'ईरानी नेतृत्व बहुत बिखरा हुआ है। इसके दो से तीन समूह हैं, शायद चार, और यह एक बहुत ही बिखरा हुआ नेतृत्व है। और यह कहने के साथ ही, वे सभी एक सौदा करना चाहते हैं, लेकिन वे सभी गड़बड़ गए हैं।'

## ईरान में बम फटने से 14 सैनिकों की मौत, यूएन चीफ बोले- प. एशिया संकट की कीमत चुका रही मानवता

तेहरान, एजेंसी। पश्चिम एशिया में 28 फरवरी से शुरू हुई जंग फिलहाल युद्धविशाल की छव में है। पदों के पीछे से अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच ईरान के जंजन शहर के पास बम फटने से रिवोल्यूशनरी गार्ड के 14 सदस्यों की मौत हो गई। ये बम युद्ध के समय के थे जो उस वक्त नहीं फटे थे। लेबनान के दक्षिणी हिस्सों में शुक्रवार को इराकल ने कम से कम आधा दर्जन हमले हुए, जिनमें अलग-अलग तरह के ढांचे और इमारतों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों की भी मौत हुई और कई घायल हुए। अल-जजीरा की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। हिजबुल्ला की ओर से कहा गया कि उसने लेबनान के अंदर इराकली सैनिकों पर कार्रवाई की। साथ ही ब्लू लाइन पार करके उत्तरी इराकल में भी कुछ हमले किए। इस इलाके में भले ही संघर्षविराम



लागू है। फिर भी हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। आज शाम कई घंटों तक बीच-बीच में धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। उन लोगों के लिए बड़ा खतरा है इराकल के बीच संघर्ष को लौट आए हैं। हजारों लेबनानी लोग पहले अपने घरों से विस्थापित हो गए थे, अब

दक्षिणी लेबनान वापस आ चुके हैं और एक कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं। सच यह है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है। हिंसक झड़पें जारी हैं। ये हिजबुल्ला और इराकल के बीच संघर्ष को लौट आने का संकेत है। लेबनान के संसद अध्यक्ष नबीह बेरी सहित कई राजनेता भी कहर रहे

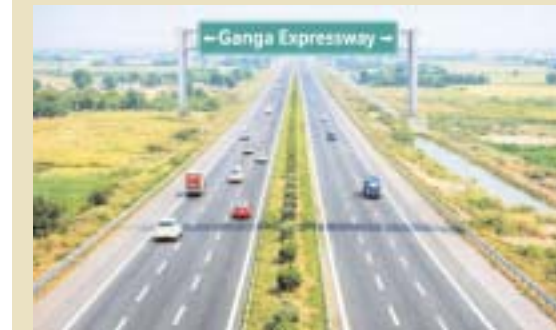
हैं कि अगर इस तरह के हमले जारी रहते हैं तो इराकल के साथ बातचीत का कोई मतलब नहीं है। हिजबुल्ला का दावा- दक्षिणी लेबनान में इराकली सेना पर किए भारी हमले: हिजबुल्ला ने शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान में इराकली सेना पर कई हमले किए हैं। लेबनान के सशस्त्र समूह ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। समूह के अनुसार, उसके लड़कों ने दक्षिणी लेबनान के कई अग्रिम इलाकों में इराकली सैनिकों और उनके वाहनों के अलग-अलग समूहों को निशाना बनाया। इनमें बिं बजेल में मूसा अब्बास काम्पलेक्स के पास तैनात सैनिकों का, तोपखाने से हमला शामिल था। हुला गांव के पास भी सैनिकों पर तोप से गोले दगे गए। इसके अलावा, बियादा इलाके में सैनिकों पर ड्रोन से हमला किया गया। अर्द्धचित अल-कुसैर में भी इसी तरह के लक्ष्य पर उचित हथियारों का इस्तेमाल

किया गया। खोर्समशहर में फंसे भारतीय नाविकों ने बताई आपबीती: ईरान में अमेरिका-इराकल युद्ध के दौरान खोर्समशहर बंदरगाह शहर में फंसे भारतीय नाविकों ने अपनी खोफनाक आपबीती बताई है। ये नाविक शुक्रवार को मुंबई हमले किए हैं। लेबनान के सशस्त्र समूह ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। समूह के अनुसार, उसके लड़कों ने दक्षिणी लेबनान के कई अग्रिम इलाकों में इराकली सैनिकों और उनके वाहनों के अलग-अलग समूहों को निशाना बनाया। इनमें बिं बजेल में मूसा अब्बास काम्पलेक्स के पास तैनात सैनिकों का, तोपखाने से हमला शामिल था। हुला गांव के पास भी सैनिकों पर तोप से गोले दगे गए। इसके अलावा, बियादा इलाके में सैनिकों पर ड्रोन से हमला किया गया। अर्द्धचित अल-कुसैर में भी इसी तरह के लक्ष्य पर उचित हथियारों का इस्तेमाल किया गया।

## लोगों को मराठी सिखाने पर राज ठाकरे स्पष्ट करें अपना रुख

धाराशिव, एजेंसी। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के अध्यक्ष राज ठाकरे को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे राज्य में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों को मराठी सिखाना चाहते हैं। उनका रुख हर दिन बदलता रहता है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कुछ जगहों पर हिंदी भाषी लोगों को मराठी सिखाने के लिए कक्षाएं शुरू कर दी हैं, लेकिन वे कहते हैं कि हिंदी भाषी लोगों को मराठी क्यों सिखाई जानी चाहिए। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मंत्री ने कहा कि राज ठाकरे को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, ताकि हम मराठी को पूरी दुनिया में फैला सकें। उनकी यह टिप्पणी गुस्से को पुनः उत्पन्न करने के लिए उभरी। राज ठाकरे को मराठी सिखाने के उद्देश्य पर स्वागत उत्ताने के बाद आई है। परिवहन मंत्रालय के उस निर्देश के बाद भाषा का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में टैक्सी और आटो रिक्शा चालकों को मराठी बोलना आना चाहिए।

## गंगा एक्सप्रेसवे में लगा रिकॉर्ड लोहा, इतने में खड़े हो जाएं 5 बुर्ज खलीफा-30 एफिल टावर, जानिए खपत



लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश का महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे अपने आकार और तकनीक के साथ-साथ निर्माण सामग्री के पैमाने को लेकर भी नए कीर्तिमान बना रहा है। इस एक्सप्रेसवे में इस्तेमाल हुआ लोहा इतना अधिक है कि उससे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जैसी करीब पांच इमारतें खड़ी की जा सकती हैं। यही नहीं, यह मात्रा एफिल टावर जैसे लगभग 30 टावर बनाने के लिए भी पर्याप्त है। यूपीइ के मुताबिक गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में करीब 2.20 लाख टन से अधिक स्टील का इस्तेमाल किया गया है। तुलना करें तो दुबई स्थित बुर्ज खलीफा के निर्माण में लगभग 55000 टन स्टील लगा था। इस हिसाब से गंगा एक्सप्रेसवे में लगा स्टील लगभग पांच बुर्ज खलीफा के बराबर है। वहीं, पेरिस के एफिल टावर में महज 7,300 टन लोहे का उपयोग हुआ था। यानी गंगा एक्सप्रेसवे में इस्तेमाल स्टील से करीब 30 एफिल टावर खड़े किए जा सकते हैं। अगर देश के अन्य बड़े प्रोजेक्ट से तुलना करें, तो द्वारका एक्सप्रेसवे में भी बड़े पैमाने पर स्टील का उपयोग हुआ, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे का आंकड़ा उससे भी कहीं अधिक है, जो इसकी विशालता को दर्शाता है। करीब 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक फैला है और 12 जिलों को जोड़ता है।

गंगा एक्सप्रेसवे की खासियत : 14 मेजर ब्रिज, 7 रेलवे ओवरब्रिज और 32 फ्लाईओवर 165 से अधिक छोटे पुल और 450 से अधिक अंडरपास लगभग 500 मिमी मोटी मल्टी-लेयर सड़क संरचना

तकनीक और गुणवत्ता में भी आगे : गंगा एक्सप्रेसवे में आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। एआई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम, स्विस सेंसर तकनीक से रियल-टाइम क्वालिटी चेक और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा सिस्टम से पूरा मार्ग लैस है। इससे न सिर्फ निर्माण की गुणवत्ता बेहतर हो रही है, बल्कि भविष्य में यात्रा भी अधिक सुरक्षित और आरामदायक होगी।

## गिरफ्तारी का कारण न बताता गैरकानूनी, हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाया 10 लाख हर्जाणा, पढ़ें पूरा केस

लखनऊ, एजेंसी। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बंदी प्रत्यकरण याचिका को स्वीकार करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध घोषित कर तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराए थे। कोर्ट ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन मानते हुए यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का हर्जाणा लगाया। कोर्ट ने सरकार को यह राशि चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को दोषी अधिकारियों से इसकी वसूली करने की छूट भी दी है।

स्टिफ्टेस अब्दुल मोईन और जस्टिस : प्रमोद कुमार वास्तव की खंडपीठ ने यह फैसला उठाया है गिरफ्तार मनोज कुमार की ओर से उसके पुत्र मुदित द्वारा दारिद्र्य याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य है कि गिरफ्तारी के आधार लिखित में दिए जाएं। दरअसल, मनोज कुमार को 27 जनवरी 2026 को थाना असीवन, जिला उन्नाव में दर्ज एक मुकदमे के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के कारण वाले कॉलम में केवल मुकदमे की अपराध संख्या दर्ज थी। इसकी बाद 28 जनवरी को मजिस्ट्रेट ने आरोपी की रिमांड मंजूर कर ली। याचिकाकर्ता ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को हाईकोर्ट में चुनौती दी और तर्क दिया कि उसे गिरफ्तारी के आधार लिखित में नहीं बताया गए, जो एक अनिवार्य संविधानिक सुरक्षा का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए रिमांड आदेश रद्द कर दिया और कहा कि यदि व्यक्ति किसी अन्य मामले में वांचित नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। साथ ही सरकार को दोषी अधिकारियों से हर्जाणा की वसूली करने की छूट दी है।

## सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 55 विद्यालयों को नोटिस, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश नहीं देना चाहते थे

लखनऊ, एजेंसी। राजधानी के नामी विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2020 (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने राजधानी के करीब 55 निजी विद्यालयों को नोटिस जारी किया है। विभाग का स्पष्ट निर्देश है, एक सप्ताह के अंदर प्रवेश न लेने वाले विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीएसए विपिन कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एल्टिडको लखनऊ पब्लिक स्कूल की अपील को खारिज करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। राजधानी में 55 ऐसे विद्यालय हैं जो आरटीई के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। विद्यालय में चयन होने के बाद भी बच्चों को प्रवेश नहीं देना चाहते हैं। इन विद्यालयों को नोटिस जारी करते हुए प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय के अनुसार, राजधानी के सिटी मॉन्टेसोरी, जयपुरिया, टीपीएस, एलपीएस, स्टडी हॉल सहित 35 से अधिक विद्यालयों को पहले से नोटिस जारी किया गया है। जबकि अन्य विद्यालयों को भी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बच्चों को प्रवेश न देने पर विद्यालय की मान्यता रद्द करने की भी प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट का ये है आदेश : हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की ओर से भेजे गए सभी बच्चों को प्रवेश देना निजी विद्यालयों का कर्तव्य है। आरटीई अधिनियम के तहत प्रत्येक विद्यालय में 25 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है।

## संजय गांधी अस्पताल में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग की बड़ी उपलब्धि

### अत्याधुनिक मशीनों से 61 जटिल जीवनरक्षक प्रक्रियाएं सफल उप मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण



**मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)**। विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में शामिल संजय गांधी अस्पताल, रीवा के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग ने चिकित्सा क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है हाल ही में स्थापित अत्याधुनिक मशीनों की मदद से विभाग ने एक माह से भी कम समय में 61 से अधिक जटिल एवं जीवनरक्षक

प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का जायजा लेने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल स्वयं अस्पताल पहुंचे और विभाग में स्थापित आधुनिक उपकरणों एवं सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने ईआरसीपी (ERCP), एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड (EUS), कोलॉन्जियोस्कोपी



और लिथोट्रिप्सी जैसी उन्नत मशीनों की कार्यप्रणाली को करीब से देखा और विभाग की कार्यक्षमता की सराहना की। अस्पताल में स्थापित अत्याधुनिक 'एडवांस्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी स्किल लैब' ने विभाग की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है इसके माध्यम से न केवल जटिल बीमारियों का उपचार संभव हुआ है बल्कि गंभीर स्थिति में

पहुंचे मरीजों के लिए यह जीवनदायिनी साबित हो रही है। विभाग द्वारा संपन्न की गई 61 प्रक्रियाओं में कई ऐसे मामले शामिल हैं जिनमें मरीजों को गंभीर रक्तस्राव की स्थिति में समय रहते एंडोस्कोपिक हीमोस्टेसिस के जरिए बचाया गया। विशेषज्ञों के अनुसार यदि यह अत्याधुनिक सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होतीं तो

मरीजों को बड़े शहरों के अस्पतालों में रेफर करना पड़ता। इससे उपचार में देरी होने के साथ ही मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ता और कई मामलों में जान का खतरा भी बना रहता। अब इन सुविधाओं के उपलब्ध होने से विंध्य क्षेत्र के मरीजों को बड़ी राहत मिली है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग वर्तमान में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. एम. एच. उस्मानी के नेतृत्व में उत्कृष्ट सेवाएं दे रहा है उनके साथ सह-प्राध्यापक डॉ. प्रदीप निगम की टीम भी पूरी दक्षता के साथ कार्य कर रही है। विभाग अब अपनी अधिकतम परिचालन क्षमता पर कार्य करते हुए उन्नत इंटरवेंशनल एंडोस्कोपी सेवाएं प्रदान करने में आत्मनिर्भर हो चुका है। इस उपलब्धि से यह स्पष्ट है कि संजय गांधी अस्पताल अब केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी उन्नत चिकित्सा सेवाओं का केंद्र

बनता जा रहा है। स्थानीय स्तर पर जटिल बीमारियों का सटीक उपचार उपलब्ध होने से मरीजों को अनावश्यक रेफरल से राहत मिल रही है और उपचार की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे आधुनिक चिकित्सा संसाधनों का विस्तार प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी किया जाएगा। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन एवं चिकित्सकों की टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट सेवाएं देने की अपेक्षा व्यक्त की। इस पहल के साथ संजय गांधी अस्पताल ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई दिशा स्थापित की है, जो न केवल विंध्य बल्कि पूरे मध्यप्रदेश के लिए गर्व का विषय है।

## राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग शोध संस्थान निर्माण को लेकर राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां तेज



**मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)**। बुद्ध जयंती के पावन अवसर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग शोध संस्थान निर्माण के संबंध में आगामी 30 एवं 31 मई 2026 को रीवा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां एवं प्रचार-प्रसार अभियान तेज गति से जारी है राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजन समिति द्वारा विभिन्न राज्य एवं सामाजिक संगठनों से संपर्क कर अधिवेशन को व्यापक एवं ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं आयोजन समिति के सदस्य किसान नेता संतकुमार पटेल, पुष्पेंद्र सिंह एडवोकेट, संजय सिंह, वी. पी. सिंह, अरुण पटेल, विपिन विश्वकर्मा, शकील खान एवं वृजेश सेन विगत 1 मई को प्रचार-प्रसार एवं जनसंपर्क अभियान के तहत प्रयागराज के

लिए रवाना हुए। प्रयागराज में आयोजित बुद्ध जयंती कार्यक्रम में शामिल होकर आयोजन समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग शोध संस्थान निर्माण की आवश्यकता एवं उसके उद्देश्य पर विस्तारपूर्वक चर्चा की कार्यक्रम में उपस्थित हजारों साधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस महत्वपूर्ण पहल को हर स्तर पर सहयोग देने का आश्वासन दिया तथा अधिवेशन में सहभागिता सुनिश्चित करने की बात कही। प्रचार-प्रसार अभियान के दौरान आयोजन समिति के सदस्यों ने 'नेशनल दस्तक' के संपादक शंभू कुमार सिंह एवं 'आर्टिकल 19' के संपादक नवीन कुमार से भी मुलाकात कर उन्हें रीवा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया।

## शहडोल के सरसी आईलैंड पर रेस्क्यू सिस्टम नहीं नाव डूबने पर बचाव मुश्किल



**मीडिया ऑडिटर, शहडोल (निप्र)**। सरसी आईलैंड की सुरक्षा व्यवस्था पर जबलपुर के बीगी डैम में क्रूज डूबने से हुई 9 मीलों के बाद गंभीर सवाल उठ रहे हैं यहां पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बुनियादी इंतजामों का अभाव है जिसमें रेस्क्यू टीम प्रशिक्षित गोताखोर और पुलिस के पास अपनी नाव न होना शामिल है। बाणसागर बैकवाटर में स्थित इस पर्यटन स्थल तक

पहुंचने के लिए पर्यटक नावों का उपयोग करते हैं हालांकि यदि बीच पानी में कोई नाव दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो तत्काल बचाव के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है सबसे नजदीकी पर्यटन थाना लगभग 10 किलोमीटर दूर है इस थाने के पास न तो अपनी नाव है और न ही प्रशिक्षित तैराक उपलब्ध हैं ऐसे में किसी भी आपदा की स्थिति में समय पर मदद मिलना

बेहद मुश्किल हो सकता है सरसी आईलैंड तक पहुंचने के लिए इटमा (लगभग 7 किमी), मार्कण्डेय (लगभग 4 किमी) और काढ़े प्वाइंट (2 से 2.5 किमी) से नावें संचालित होती हैं। ये सभी मार्ग जलमार्ग हैं जिससे आपात स्थिति में राहत दल या पुलिस के पहुंचने में देरी होना तय है। पर्यटन पुलिस ने स्वीकार किया है कि किसी भी आपदा की स्थिति में उन्हें मौके पर मौजूद निजी नावों पर निर्भर रहना पड़ता है विभाग के पास न तो अपनी नाव है और न ही कोई विशेष रेस्क्यू टीम या गोताखोर उपलब्ध हैं आईलैंड प्रबंधन के अनुसार उनके पास कुल 5 नावें हैं जिनमें एक वाटर स्कूटर और 18 लोगों की क्षमता वाली

जलपरी नाव शामिल है प्रबंधन का दावा है कि बिना लाइफ जैकेट किसी भी पर्यटक को नाव में बैठने नहीं दिया जाता और एक नाव हमेशा स्टैंडबाय में रखी जाती है। हालांकि प्रबंधन ने यह भी स्वीकार किया कि उनके पास कोई अलग रेस्क्यू दल नहीं है जल्द ही बचाव कार्य करते हैं जिन्हें सीमित प्रशिक्षण दिया गया है। एसडीआरएफ के अनुसार उनकी 8 सदस्यीय टीम शहडोल मुख्यालय में तैनात है जो सरसी आईलैंड से लगभग 125 किलोमीटर दूर है ऐसे में किसी बड़े हादसे की स्थिति में राहत और बचाव दल को मौके पर पहुंचने में काफी समय लग सकता है।

## मजदूर दिवस पर ब्रह्मा कुमारी कलम परिवार ने किया सम्मान



**मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)**। श्रम के पसोंने की कद्र आज सारा विश्व करता है, क्योंकि बिना श्रमिक वर्ग के योगदान के किसी भी क्षेत्र में विकास की योजनाओं को संचालित करना संभव नहीं है। यह विचार मजदूर दिवस के अवसर पर शांतिधाम में आयोजित एक यादगार कार्यक्रम में संजय गांधी अस्पताल के पूर्व संचालक डॉ. सी.बी. शुक्ला ने व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कलम परिवार

के संस्थापक नारायण डिग्वानी ने कहा कि आज मजदूर बहुमुखी प्रतिभाओं का धनी हो गया है वह किसी भी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के बाद किसी भी हुरार के साथ अपनी पहचान रखता है। इस दौरान विशिष्ट अतिथि हिन्दू धर्म परिषद के मार्गदर्शक डी.पी. सिंह परिहार ने बताया कि समूचे विश्व की नामी इमारतों और उद्योगों के निर्माण में मजदूरों का अहम योगदान है जिससे उनकी परिभाषा भी विस्तारित हुई है। कार्यक्रम में

बवेली सेवा मंच के अध्यक्ष भृगुनाथ पाण्डेय भ्रमर ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आयोजन साहित्यिक चैतन्यता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम मजदूर दिवस पर एक समर्पित प्रयास है। कार्यक्रम के संचालन में राजयोगिनी बी.के. निर्मला ब्रह्मा कुमारी कला संस्कृति प्रभाग मध्य प्रदेश की जोनल डायरेक्टर, स्थानीय संचालिका बी.के. लता और संयोजक बी.के. प्रकाश के मार्गदर्शन में विंध्य काव्य साहित्य परिषद के अध्यक्ष नागेन्द्र मिश्रा मणी ने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाया महासचिव रामकृष्ण द्विवेदी ने स्वागत उद्बोधन दिया और आभार प्रदर्शन डॉ. गीता शुक्ला गीत ने किया।

## विज्ञान को रोचक बनाने की पहल शिक्षकों को मिला प्रयोगात्मक प्रशिक्षण

**मीडिया ऑडिटर, सीधी (निप्र)**। विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने एवं शिक्षण को अधिक व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से जिले के शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए तीन दिवसीय प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण जिला उत्कृष्ट विद्यालय सीधी में जिला शिक्षा अधिकारी पवन कुमार सिंह के निर्देशन तथा एडीपीसी ओशो कस्तुर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें सीधी एवं सिहावल विकासखंड के शिक्षकों का प्रशिक्षण 21 से 23 अप्रैल तथा कुसमी, मझौली एवं रामपुर नैकिन विकासखंड के शिक्षकों का प्रशिक्षण 24 से 26 अप्रैल 2026 तक कराया गया। डाइट प्राचार्य एस. केरकेड्रा एवं शम्भुनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में मास्टर ट्रेनर अमित सिंह द्वारा शिक्षकों को प्रायोगिक शिक्षण के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई एपीसी रमसा डॉ. सुजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक प्रयोगशाला गतिविधियों में भाग लिया और नई शिक्षण विधियों को सीखा उन्हें प्रयोगशाला उपकरणों के सही उपयोग सुरक्षा मानकों के पालन तथा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के प्रभावी तरीकों की जानकारी भी दी गई प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के प्रायोगिक ज्ञान को सुदृढ़ करना और विज्ञान शिक्षण को अधिक रोचक, सरल एवं प्रयोग आधारित बनाना रहा। यह पहल जिले में विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

## निगाही प्लांट में आदिवासी युवक से मारपीट सिक्वोरिटी इंचार्ज पर केस दर्ज

**मीडिया ऑडिटर, सिंगरौली (निप्र)**। जिले की नॉर्दन कोलफील्ड लिमिटेड (एनसीएल) के निगाही कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) क्षेत्र से एक आदिवासी युवक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है इस मामले में नवानगर थाना में सिक्वोरिटी इंचार्ज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है पुलिस ने पीड़ित युवक की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कथित तौर पर सिक्वोरिटी इंचार्ज हॉकी स्टिक से बैग समुदाय के युवक अन्ने लाल बैग को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं यह घटना निगाही सीएचपी क्षेत्र में हुई थी। जानकारी के अनुसार यह वीडियो लगभग दो महीने पुराना बताया जा रहा है लेकिन हाल ही में सामने आने के बाद यह



मामला गरमा गया नवानगर थाना प्रभारी अनिल पटेल ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया गया है उन्होंने यह भी कहा कि यदि पीड़ित ने पहले शिकायत की होती तो तत्काल कार्रवाई की जाती। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अन्ने लाल बैग कथित तौर पर शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ सीएचपी क्षेत्र से लोहे का सामान उठा रहा था सुरक्षा

कर्मियों ने उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माना इसके बाद सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और आदिवासी समुदाय में नाराजगी देखी जा रही है।

## अस्पताल चौराहा में उमड़ा श्रमिकों का जनसैलाब द्वादश ज्योतिर्लिंग झांकी व नशा मुक्ति का संदेश

मजदूर दिवस पर ब्रह्माकुमारीज द्वारा भव्य आयोजन, श्रमिक सम्मान के साथ आध्यात्मिक जागरण का आह्वान

**मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)**। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर ब्रह्माकुमारीज रीवा द्वारा अस्पताल चौराहा परिसर में एक भव्य एवं भावपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस आयोजन में हजारों की संख्या में श्रमिक भाई-बहनों की गरिमायुगी उपस्थिति रही। कार्यक्रम श्रम सम्मान, आध्यात्मिक जागरण और सामाजिक परिवर्तन का प्रेरणादायक संगम बनकर सामने आया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सभापति नगर निगमसतीश सोनी उपस्थित रहे जबकि अध्यक्षता पूजा प्रमोद सिंह ने की इस अवसर पर श्रमिकों के परिश्रम, उनकी सहनशीलता एवं राष्ट्र निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को



सराहा गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रमिकों का सम्मान कर उनका आत्मबल बढ़ाया गया साथ ही ब्रह्माकुमारी परिवार द्वारा लक्ष्मी-नारायण का दिव्य कार्ड शिव संदेश एवं राजयोग मेडिटेशन का परिचय दिया गया तथा चरित्र निर्माण प्रदर्शनी के माध्यम से जीवन मूल्यों का संदेश प्रसारित किया गया। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में वार्ड क्रमांक 21 के पार्थदसंजय खान मुख्य अतिथि के

रूप में उपस्थित रहे तथा अध्यक्षता ब्रह्माकुमारीज रीवा की संचालिका बी.के. लता दीदी ने की विशिष्ट अतिथियों मेंअवधेश वास्तव एवंअंकु तिवारी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही इस दौरान श्रमिकों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन को श्रेष्ठ बनाने एवं नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की दिव्य झांकी रही

जिसके दर्शन कर उपस्थित जनसमूह भावविभोर हो उठ वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत हो गया और सभी ने आत्मिक शांति का अनुभव किया कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रसाद स्वरूप मीठी टोली वितरित की गई यह आयोजन भोपाल जोन डायरेक्टर राजयोगिनी बी.के. निर्मला बहन जी के निर्देशन में सम्पन्न हुआ, जिसमें बी.के. विजयदेव, बी.के. सतेन्द्र, बी.के. सुशील, बी.के. जगदीश, बी.के. सुरेन्द्र, बी.के. रोहित, बी.के. रुद्र एवं बी.के. सुभाष सहित अनेक सदस्यों का योगदान रहा। यह आयोजन केवल मजदूर दिवस का उत्सव नहीं बल्कि श्रमिकों के सम्मान, आत्मबल जागरण और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में एक सार्थक पहल सिद्ध हुआ।

## 10वीं-12वीं में 16 शासकीय स्कूलों का 100 रिजल्ट 98 स्कूलों ने 90 से अधिक सफलता पाई

**मीडिया ऑडिटर, सीधी (निप्र)**। वर्ष 2026 के बोर्ड परीक्षा परिणामों में सीधी जिले ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रदेश में अपनी मजबूत पहचान बनाई है कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के परिणामों में जिले को अग्रणी जिलों की श्रेणी में ला खड़ा किया है कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में जिले ने 81.61 प्रतिशत सफलता हासिल की, जो पिछले वर्ष के 81.21 प्रतिशत से अधिक है यह प्रदेश के औसत 73.42 प्रतिशत से भी काफी बेहतर है। इस प्रदर्शन के साथ जिले ने प्रदेश में 14वां स्थान प्राप्त किया है साथ ही कई विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में स्थान बनाकर जिले का नाम रोशन किया है। वहीं कक्षा 12वीं के परिणाम में भी जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 90 प्रतिशत सफलता दर्ज की जो प्रदेश के औसत 76.1 प्रतिशत से कहीं अधिक है इस उपलब्धि के साथ सीधी जिले ने प्रदेश में लगातार

पांचवां स्थान बनाए रखा है। जिले के शासकीय विद्यालयों का प्रदर्शन भी बेहद सरहनीय रहा कक्षा 10वीं एवं 12वीं को मिलाकर 16 विद्यालयों ने 100 प्रतिशत परिणाम हासिल किया जबकि 98 विद्यालयों का परिणाम 90 प्रतिशत से अधिक रहा। कक्षा 12वीं में 53 विद्यालयों ने 90 प्रतिशत से अधिक और 4 विद्यालयों ने 100 प्रतिशत परिणाम प्राप्त किया उल्लेखनीय है कि किसी भी विद्यालय का परिणाम 30 प्रतिशत से कम नहीं रहा जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है। एपीसी रमसा डॉ. सुजीत कुमार मिश्र के अनुसार इस सफलता के पीछे वर्षभर चलाए गए शैक्षणिक सुधार कार्यक्रम, रेमेडियल कक्षाएं, नियमित मॉनिटरिंग, शिक्षक प्रशिक्षण, कैरियर काउंसलिंग, प्रायोगिक गतिविधियों पर जोर और विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

## प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस सीधी में विश्व रेडक्रॉस सप्ताह का शुभारंभ

मानवता में एकजुटता थीम पर जागरूकता अभियान छात्रों को सेवा और संवेदनशीलता का संदेश

**मीडिया ऑडिटर, सीधी (निप्र)**। मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 2 मई से 8 मई 2026 तक मनाए जा रहे विश्व रेडक्रॉस सप्ताह के तहत सीधी जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है इसी क्रम में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस, संजय गांधी स्मृति शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी में रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस वर्ष रेडक्रॉस सप्ताह की थीम मानवता में एकजुटता/मानवता के लिए संगठित रखी गई है जिसका उद्देश्य समाज में सेवा, सहयोग और संवेदनशीलता को भावना को बढ़ावा देना है कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रभाकर सिंह ने विद्यार्थियों को



संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में संकट की घड़ी में घबराने के बजाय जागरूकता और सृष्टिवृद्ध से काम लेना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते

हुए कहा कि रेडक्रॉस जैसे संगठन हमें मानव सेवा आपदा प्रबंधन और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति सजग बनाते हैं। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रेडक्रॉस सोसाइटी के

सदस्य अमित प्रधान ने रेडक्रॉस दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह सप्ताह न केवल सेवा कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर है बल्कि यह हमें

एक-दूसरे की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहने की सीख भी देता है। उन्होंने रेडक्रॉस की गतिविधियों आपदा राहत कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार आपदा के समय बचाव के उपाय तथा समाज सेवा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी दी गई इस दौरान छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सेवा भावना को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के दिवस प्रभारी के रूप में रेडक्रॉस सोसाइटी के सदस्य डॉ. मनोला सिंह, एनसीसी अधिकारी डॉ. उमाकांत साहू, डॉ. राजकुमार सिंह सोर्टिया, डॉ. प्रतिभा सिंह सहित महाविद्यालय के अन्य

प्राध्यापक उपस्थित रहे कार्यक्रम में सैकड़ों विद्यार्थियों की सहभागिता ने इसे और अधिक प्रभावशाली बना दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन महाविद्यालय के क्रीडा अधिकारी डॉ. रविंद्रनाथ सिंह द्वारा किया गया आयोजन के अंत में सभी प्रतिभागियों को मानवता, सेवा और सहयोग के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया रेडक्रॉस सप्ताह के तहत आगामी दिनों में भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी जिनमें स्वास्थ्य जागरूकता, रक्तदान, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण एवं सामाजिक सेवा से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। यह पहल निश्चित रूप से युवाओं को समाज के प्रति उत्पन्न की जिम्मेदारियों को समझने और एक बेहतर नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करेगी।

## शोर का न ओर-छोर : ध्वनि प्रदूषण का सेहत पर घातक असर

यू तो हाल के वर्षों में आम भारतीय की अभिव्यक्ति में तलखी व शोर का ग्राफ तेज हुआ है। अभिव्यक्ति का मुखर होना अच्छा है लेकिन उसका तलख होना, किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जैसे हमारे परिवेश में लगातार बढ़ता शोर झेलना हमारी निर्यति हो चला है। सड़कों पर वाहनों के शोर, नये दौर के कर्कश संगीत से लेकर राजनीतिक विमर्श में होने वाले शोरगुल वाले संवाद से लेकर तमाम ऐसा कुछ घट रहा है, जो हमारी परेशानी

का सबब बन रहा है। यू तो कोई प्रमाणिक राष्ट्रव्यापी वैज्ञानिक शोध व्यापक रूप में हमारे सामने तो नहीं आए हैं जो ठीक-ठीक बताएं कि ध्वनि प्रदूषण हमारी सेहत पर कितना घातक असर डाल रहा है। लेकिन गुण-बगाने सामने आए आंकड़े इस बात की पुष्टि जरूर करते हैं कि लगातार बढ़ता शोर हमारी सेहत बिगाड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद इसे रोकने के लिए उचित निगरानी, समयबद्ध कार्रवाई और दंड के प्रावधान लागू होते नजर

नहीं आते हैं। लेकिन विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्ष बता रहे हैं देश के महानगरों से लेकर कस्बों तक हमारे परिवेश का शोर तय मानकों से कहीं अधिक है। जाहिरा तौर पर शोर हमारी सेहत को गहरे तक प्रभावित कर रहा है। जिससे न केवल हमारी श्रवण शक्ति कमजोर हो रही है बल्कि नींद में कमी, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप

के अलावा हृदय रोग तक का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन इस दिशा में कार्रवायों में तो लुभावनी योजनाएं तो बनायी जाती हैं लेकिन जमीनी हकीकत बदलती नजर नहीं आती। यह सुखद है कि पिछले दिनों देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस दिशा में नई पहल शुरू की गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने ध्वनि प्रदूषण

नियंत्रण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया आरंभ की है। दावा किया जा रहा है कि प्रदूषण के स्रोतों को कायदे से निगरानी होगी। इसके अलावा समयबद्ध ढंग से कार्रवाई होगी। साथ ही जुर्माना भी अनिवार्य रूप से वसूला जाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अच्छी योजना कितनी जमीनी हकीकत बनती है। लेकिन सवाल यह है कि जब देश में पहले से शोर नियंत्रण के कानून मौजूद हैं और

हमारी अदालतें भी समय-समय पर हमारे नीति नियंताओं को आगाह करती ही रहती हैं, तो फिर सूरत क्यों नहीं बदलती। आखिर इन नियम-कानूनों के क्रियान्वयन में कहाँ खोटा रह जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम, 2000 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों, निर्माण कार्यों और उद्योगों में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों, वाहनों के हॉर्न आदि अन्य स्रोतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था।

### संपादकीय

## स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की सेहत का आईना

सौरभ वाषण्य

प्रत्येक वर्ष 3 मई को पूरे विश्व में प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह केवल एक औपचारिक अवसर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सेहत का आईना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक मीडिया किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। प्रेस की आजादी सिर्फ पत्रकारों का अधिकार नहीं, बल्कि नागरिकों के जानने के अधिकार का विस्तार है। वहीं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 157 वें स्थान पर है। पिछले वर्ष (2025) के 151वें स्थान की तुलना में यह छह पायदान की गिरावट है। भारत में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, मीडिया के केंद्रीकृत स्वामित्व और राजनीतिक दबाव के कारण यह रैंकिंग बेहद गंभीर श्रेणी में है।

आज जब दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है, सूचना का प्रवाह पहले से कहीं अधिक तेज और व्यापक हो गया है। लेकिन इसी के साथ प्रेस की स्वतंत्रता पर नए प्रकार के खतरों भी मंडरा रहे हैं। फेक न्यूज, टेलर संस्कृति, सत्ता का दबाव, कॉर्पोरेट हितों का प्रभाव और पत्रकारों की सुरक्षा जैसे मुद्दे गंभीर चुनौती बनकर उभरे हैं। कई देशों में पत्रकारों को सचवाई उजागर करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है—यह स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंताजनक है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां प्रेस न केवल सत्ता की निगरानी करता है, बल्कि समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज भी बनाता है। हालांकि, हाल के वर्षों में यह बहस तेज हुई है कि क्या मीडिया अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने में पूरी तरह सफल है? गोडो मीडिया जैसे शब्दों का प्रचलन इस चिंता को दर्शाता है कि कहीं न कहीं मीडिया का एक वर्ग सत्ता के अधिक निकट जाता दिख रहा है।

प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि वह बिना जिम्मेदारी के कार्य करे। स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी जुड़ी होती है। पत्रकारिता का मूल धर्म सत्य की खोज, तथ्यों की पुष्टि और निष्पक्ष प्रस्तुति है। जब मीडिया सनसनीखेजता या पक्षपात की ओर झुकता है, तो वह अपने ही अस्तित्व को कमजोर करता है।

इस अवसर पर सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे पत्रकारों को सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण प्रदान करें, जहां वे बिना भय के अपना कार्य कर सकें। वहीं, मीडिया संस्थानों को भी आत्ममंथन करना होगा कि वे व्यावसायिक दबावों से ऊपर उठकर जनहित को प्राथमिकता दें। लोकतंत्र को जीवित रखना है, तो उसकी आवाज को स्वतंत्र रखना ही होगा। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। लोकतंत्र किसी भवन की तरह है, जिसकी नींव जनता की भागीदारी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर टिकी होती है। यदि इस अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाया जाए, तो लोकतंत्र का ढांचा धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है। स्वतंत्र आवाज केवल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक के विचार, प्रश्न और असहमति को व्यक्त करने के अधिकार का प्रतीक है। जब नागरिक बिना भय के अपनी बात कह पाते हैं, तभी सरकारें जवाबदेह बनती हैं और नीतियों में परिवर्तन आती हैं। इसके विपरीत, जब आवाजों को दबाया जाता है, तो सत्ता निरंकुशता की ओर बढ़ने लगती है। आज के समय में यह चुनौती और भी जटिल हो गई है। एक ओर डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अभिव्यक्ति के नए अवसर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर दुष्प्रचार, ट्रोलिंग और सेंसरशिप जैसी प्रवृत्तियां भी सामने आई हैं। ऐसे में संतुलन बनाना आवश्यक है—जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे, वहीं जिम्मेदारी और सत्यनिष्ठा भी सुनिश्चित हो। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता; यह निरंतर संवाद, आलोचना और विचार-विमर्श की प्रक्रिया है। इसलिए जरूरी है कि हम न केवल अपनी आवाज को स्वतंत्र रखें, बल्कि दूसरों की आवाज को सुनने और सम्मान देने की संस्कृति भी विकसित करें। लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी आवाज कितनी स्वतंत्र, निष्पक्ष और सशक्त है। यदि यह आवाज जीवित और निर्भीक है, तो लोकतंत्र भी जीवित और सशक्त रहेगा। प्रेस की स्वतंत्रता केवल कानूनों से नहीं, बल्कि समाज की जागरूकता और समर्थन से भी सुरक्षित रहती है।

## अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम हेट स्पीच- डिजिटल युग में हेट स्पीच दंगों व नफरतों को खुला आमंत्रण- कानून पर्याप्त या क्रियान्वयन की चुनौती?

सुप्रीम कोर्ट के 29 अप्रैल 2026 फैसले का व्यापक विश्लेषण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(डू) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) के तहत इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं हेट स्पीच केवल एक कानूनी समस्या नहीं है यह एक सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक चुनौती भी है, भारत में कानूनों की कमी नहीं है, बल्कि उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने की वह सख्ती से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है

### एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तर पर संचार क्रांति ने जिस गति से समाज को बदला है, वह अभूतपूर्व है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और 24x7 ब्रॉडकास्ट मीडिया के विस्तार ने सूचना के प्रवाह को इतना तेज बना दिया है कि अब किसी व्यक्ति, चाहे वह आम नागरिक हो, राजनीतिक नेता हो या धार्मिक वक्ता, इनका एक शब्द भी कुछ ही मिनटों में लाखों-करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। यह तकनीकी प्रगति जहां लोकतंत्र को मजबूत करने, विचारों के आदान-प्रदान और पारदर्शिता बढ़ाने का माध्यम बनी है, वहीं इसके नकारात्मक पहलू भी उत्पन्न हो रहे हैं। खासकर हेट स्पीच याने नफरत फैलाने वाले भाषणों ने सामाजिक सौहार्द, धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे की भावना के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर दी है। एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महापट्ट पर धमना हूँ कि जब कोई इनकार करते हुए स्पष्ट कहा कि मौजूदा कानूनी ढांचा इन अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि समस्या कानून की कमी नहीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन की है। यह निर्णय केवल कानूनी नैतिकता से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र में शक्तिशाली के पृथक्करण न्यायिक हस्तक्षेप की मांग तेज हुई है। इसी



पृष्ठभूमि में 29 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसने इस बहस को नई दिशा दी। अदालत ने हेट स्पीच को रोकने के लिए नए दिशानिर्देश बनाए या अतिरिक्त न्यायिक हस्तक्षेप से इनकार करते हुए स्पष्ट कहा कि मौजूदा कानूनी ढांचा इन अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त है। सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही नफरत की पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि समस्या कानून की कमी नहीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन की है। यह निर्णय केवल कानूनी नैतिकता से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र में शक्तिशाली के पृथक्करण न्यायिक हस्तक्षेप की मांग तेज हुई है। इसी

बोध संतुलन को भी स्पष्ट करता है। साथियों बात अगर हम हेट स्पीच के खिलाफ दायर याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने तर्क को समझने की करें तो उन्होंने तर्क दिया था कि वर्तमान कानून अस्पष्ट हैं और उनका प्रभावी तरीके से पालन नहीं हो रहा है। उनका कहना था कि राजनीतिक भाषणों, धार्मिक सभाओं और सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही नफरत समाज में विभाजन को बढ़ा रही है और इसके लिए एक स्पष्ट, सख्त और समग्र कानून की आवश्यकता है। कोरोना जिहाद जैसे विवादित टैगलाइन्स और विभिन्न धार्मिक मंचों से दिए गए भड़काऊ भाषणों का उदाहरण देते हुए उन्होंने अदालत से मांग की थी कि वह इस दिशा में

ठोस दिशानिर्देश जारी करें। लेकिन अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया और दोहराया कि कानून बनाने का अधिकार संसद और न्यायपालिका के पास है, न कि न्यायपालिका के पास। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संवैधानिक न्यायालय कानून की व्याख्या कर सकते हैं और मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हैं, लेकिन वे खुद कानून नहीं बना सकते।

साथियों बात अगर हम इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू को समझने की करें तो वह यह है कि अदालत ने भारतीय न्यायिक परंपरा को कायम रखते हुए विधायी शून्य (लैजिस्लेटिव वेक्यूम) की अवधारणा को खारिज किया। अदालत ने कहा कि भारत में पहले से ही ऐसे कई कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, जो हेट स्पीच से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। उदाहरण के तौर पर, भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराएं जैसे धारा 196 (वैमनस्य फैलाना), धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और अन्य प्रावधान स्पष्ट रूप से इस तरह के अपराधों को कवर करते हैं। इसके अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में भी ऐसे प्रावधान हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि संज्ञेय अपराधों के मामलों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य हो। अदालत ने यह भी बताया कि यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में

विफल रहती है, तो पीड़ित व्यक्ति पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट के पास जाकर न्याय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार, कानूनी ढांचे में पर्याप्त उपाय मौजूद हैं, जरूरत है तो केवल उनके सही और समय पर उपयोग की। हालांकि अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि यदि बदलते समय और सामाजिक चुनौतियों के अनुसार नए कानूनों या संशोधनों की आवश्यकता महसूस होती है, तो केंद्र और राज्य सरकारें इस पर विचार कर सकती हैं। इस संदर्भ में 2017 की लॉ कमीशन रिपोर्ट का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है, जिसमें हेट स्पीच से संबंधित कानूनों को और स्पष्ट करने के सुझाव दिए गए थे। लेकिन अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह निर्णय विधायिका के विवेक पर निर्भर करता है, न कि न्यायपालिका के निर्देश पर। साथियों बात अगर हम इस पूरे मामले में सबसे जटिल और महत्वपूर्ण सवाल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हेट स्पीच के बीच संतुलन का है इसको समझने की करें तो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) के तहत इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में।

## सूचना की दौड़ में ज्ञान का क्षरण: सोशल मीडिया और आज का युवा

रवि मिश्रा

(राष्ट्रीय वक्ता, स्वयंसेवक - राष्ट्रीय सेवा योजना)

तकनीकी के तीव्र विस्तार ने समाज को अभूतपूर्व गति दी है। इसी प्रक्रिया में सोशल मीडिया संवाद, अभिव्यक्ति और प्रचार-प्रसार का एक शक्तिशाली माध्यम बनकर उभरा है। किंतु इसका अनियंत्रित और अत्यधिक उपयोग आज विशेषकर युवाओं के लिए एक गंभीर सामाजिक और मानसिक चुनौती का रूप लेता जा रहा है। जेन-जी के बीच सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव केवल व्यवहारिक परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनकी सोच, अध्ययन पद्धति और जीवनशैली को भी गहराई से प्रभावित कर रहा है। पढ़ने से चौबीस वर्ष की आयु, जिसे जीवन की सबसे ऊर्जावान और संभावनाओं से परिपूर्ण अवस्था माना जाता है, आज 'तत्काल संतुष्टि' और उच्च डोपामिन-आधारित डिजिटल आदतों के प्रभाव में आ रही है। गैल्स और शॉर्ट कंटेंट के निरंतर उपभोग ने युवाओं की एकाग्रता, धैर्य और विश्लेषणात्मक

क्षमता को कमजोर किया है। यह प्रवृत्ति गहन अध्ययन और दीर्घकालिक चिंतन की संस्कृति को हाशिए पर धकेल रही है, जिसके परिणामस्वरूप ज्ञान का स्थान सतही सूचना ने ले लिया है।

इस परिवर्तन का सबसे स्पष्ट प्रभाव युवाओं की दिनचर्या में दिखाई देता है। जहाँ स्वस्थ जीवन के लिए 7-8 घंटे की नींद आवश्यक मानी जाती है, वहीं वर्तमान में अनेक विद्यार्थियों की नींद 4-5 घंटे तक सीमित हो गई है। पारंपरिक रूप से ब्रह्ममूहूर्त को अध्ययन और आत्म-विकास का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है, किंतु आज का विद्यार्थी उसी समय सोने की प्रवृत्ति विकसित कर रहा है। यह असंतुलित जीवनशैली न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, बल्कि मानसिक एकाग्रता, उत्पादकता और निर्णय-क्षमता को भी कमजोर बना रही है। 'सूचना की दौड़ में ज्ञान का क्षरण' इस परिघटना का केंद्रीय तत्व है। डिजिटल माध्यमों ने सूचना की उपलब्धता को सहज और तबू बनाया है, किंतु इसी के साथ ज्ञान के गहन आगमों को सीमित कर दिया है। आज का युवा बड़ी मात्रा

में जानकारी एकत्र तो कर रहा है, परंतु उसके विश्लेषण, आत्मसात और अनुप्रयोग की क्षमता में कमी देखी जा रही है। यही कारण है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में लाइब्रेरियाँ, जो कभी चिंतन और बौद्धिक विमर्श का केंद्र हुआ करती थीं, आज अपेक्षाकृत निष्क्रिय होती जा रही हैं।

शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव और अधिक स्पष्ट होता है। जहाँ पहले कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाओं में पुस्तकों का अध्ययन मुख्य आधार होता था, वहीं आज उस स्थान को इंटरनेट ने काफी हद तक प्रतिस्थापित कर दिया है। परिणामस्वरूप, विद्यार्थियों के पास सूचना का भंडार तो है, किंतु विषय की गहराई और वैचारिक स्पष्टता का अभाव दिखाई देता है। अनेक संस्थानों में विद्यार्थियों के परिणामों में गिरावट इस प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया की संरचना स्वयं प्रतिस्पर्धा और तुलना को बढ़ावा देती है। 'लाइक' और 'फॉलोअर्स' की संस्कृति, दिखावटी जीवनशैली और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएँ युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। आत्मविश्वास में कमी,

अकेलापन और सामाजिक अलगाव जैसी स्थितियाँ तेजी से उभर रही हैं। प्रतिदिन 8 से 9 घंटे तक का स्क्रीन टाइम इस संकेत की गंभीरता को और अधिक स्पष्ट करता है।

जीवन के संतुलन के लिए प्रचलित '8-8-8' सिद्धांत—8 घंटे नींद, 8 घंटे कार्य/अध्ययन और 8 घंटे विश्राम या शारीरिक गतिविधि—आज के संदर्भ में लगभग अप्रासंगिक होता जा रहा है। डिजिटल निर्भरता ने इस सिद्धांत को भंग कर दिया है, जिससे युवा वर्ग का समग्र विकास बाधित हो रहा है। अतः यह निष्कर्ष स्पष्ट है कि समस्या सोशल मीडिया के अस्तित्व में नहीं, बल्कि उसके अनियंत्रित और अत्यधिक उपयोग में निहित है। आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली, अभिभावक और स्वयं युवा इस चुनौती को समझते हुए डिजिटल अनुशासन और संतुलन को अपनाएं। सोशल मीडिया का विवेकपूर्ण उपयोग यदि ज्ञान, कौशल और रचनात्मकता के विकास में किया जाए, तो यह एक सशक्त साधन सिद्ध हो सकता है; अन्यथा यह युवा शक्ति की अपार संभावनाओं को क्षीण करने वाला एक गहन सामाजिक संकट बन जाएगा।

## पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पर हमला और चुनावी प्रक्रिया की साख पर सवाल

पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी परिदृश्य ने एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र के सामने गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। जिस प्रक्रिया को संविधान ने जनता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति का माध्यम माना है, उसी प्रक्रिया के दौरान हिंसा, मारपीट, डराने-धमकाने और चुनावी मशीनों से छेड़छाड़ जैसे आरोप सामने आना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। हाल के घटनाक्रमों में भाजपा कार्यकर्ताओं और उन्नावीदारों पर हमले, बूथों पर तब्दी और ईवीएम के साथ कथित छेड़छाड़ की खबरें इस बात का संकेत देती हैं कि चुनाव केवल मतदान का कार्य नहीं रह गया है बल्कि शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बनता जा रहा है।

कान्तिराल मांडे

इन घटनाओं के केंद्र में राजनीतिक दलों के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा तो है ही, लेकिन उससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि क्या मतदाता वास्तव में बिना भय के अपना मत/विकार इस्तेमाल कर पा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप लगाते सामने आ रहे हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों पर हिंसा फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह स्थिति केवल राजनीतिक टकराव नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा है।

चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाएँ नई नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से बूथ स्तर पर एजेंटों को निशाना बनाया गया, उम्मीदवारों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और खुलेआम मारपीट हुई, वह यह दर्शाता है कि कानून और व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि हर नागरिक बिना किसी दबाव के अपने मत का प्रयोग करे। लेकिन जब किसी पोलिंग एजेंट को घायल कर दिया जाता है या किसी उम्मीदवार को मतदान केंद्र के आसपास घेर लिया जाता है, तो यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर आघात है।

सबसे गंभीर आरोप ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सामने आए हैं। यदि किसी भी मतदान केंद्र पर किसी विशेष पार्टी के चुनाव



चिन्ह के सामने टेप लगाया जाता है, तो यह केवल तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि मतदाता की स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास माना जाएगा। इस प्रकार की घटनाएँ लोकतंत्र की आत्मा के विपरीत हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कहा है कि जहाँ भी ऐसी शिकायतें सही पाई जाएँ, वहाँ पुनर्मतदान कराया जाएगा। यह कदम आवश्यक है, लेकिन इससे यह सवाल भी उठता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई। राजनीतिक बयानबाजी भी इस पूरे माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना रही है। मतदाता बनने के नेतृत्व वाली सरकार पर विश्वास लगाए



आरोप लगा रहा है कि राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं सत्ताधारी दल इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज करता है। इस आरोप-प्रत्यारोप के बीच असली मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है, जो है आम मतदाता की सुरक्षा और स्वतंत्रता। चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह जनता के विश्वास का प्रतीक होता है। यदि इस प्रक्रिया में हिंसा और डर का माहौल हावी हो जाए, तो यह विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। पश्चिम बंगाल में सामने आई घटनाएँ यह संकेत देती हैं कि राजनीतिक दलों

को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। किसी भी दल की जीत या हार से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि लोकतंत्र केवल संस्थाओं से नहीं चलता, बल्कि उसमें भाग लेने वाले सभी पक्षों की जिम्मेदारी होती है। राजनीतिक दलों, प्रशासन, सुरक्षा बलों और मतदाताओं सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होता है कि चुनाव एक उत्सव की तरह संपन्न हो, न कि संघर्ष के मैदान की तरह। जब कार्यकर्ता हिंसा का सहारा लेते हैं, तो वे अपने ही लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करते हैं।

पश्चिम बंगाल की राजनीतिक संस्कृति लंबे समय से संघर्ष और प्रतिस्पर्धा से भरी रही है। लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में इस प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्तियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर यह साबित करने के लिए जानबूझकर हिंसा या तकनीकी छेड़छाड़ की गई, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई आवश्यक है। केवल पुनर्मतदान कराना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि दोषियों को सजा देना भी उचित ही जरूरी है।

इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जनता का भरोसा। जब लोग यह सुनते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई या किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मतदान से रोका गया,

तो उनके मन में संदेह उत्पन्न होता है। यह संदेह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यदि जनता का विश्वास ही डगमगा जाए, तो चुनाव का महत्व कम हो जाता है।

इसलिए आवश्यक है कि सभी बंध संयम बरते और चुनाव आयोग को पूरी स्वतंत्रता और सहयोग दिया जाए। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा को रोका जा सके। साथ ही राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि वे कानून का पालन करें और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करें।

अंततः यह समझना होगा कि लोकतंत्र केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। पश्चिम बंगाल में जो घटनाएँ सामने आई हैं, वे केवल एक राज्य का मामला नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चेतावनी हैं। यदि हम इन घटनाओं से सबक नहीं लेते, तो भविष्य में ऐसी परिस्थितियाँ और अधिक गंभीर हो सकती हैं।

लोकतंत्र की रक्षा केवल कानून से नहीं बल्कि आचरण से होती है। जब तक राजनीतिक दल अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाते और हिंसा से दूरी नहीं बनाते, तब तक ऐसी घटनाएँ दोहराई जाती रहेंगी। अब समय आ गया है कि चुनाव को संघर्ष नहीं बल्कि विश्वास और सहभागिता का माध्यम बनाया जाए, ताकि भारत का लोकतंत्र और अधिक मजबूत बन सके।

## जिला एमसीबी को स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी सफलता

## आयुष्मान आरोग्य मंदिर छिपछिपी को मिला NQAS प्रमाणन गुणवत्ता सेवाओं की मिली पहचान



**मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)**। जिला (एमसीबी) में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लगातार सुधार और सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है जिले के अंतर्गत संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर छिपछिपी को

राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाणन प्राप्त हुआ है जो स्वास्थ्य सेवाओं की उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रमाण है। यह उपलब्धि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन एवं प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है जिनके



नेतृत्व में जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर बेहतर बनाया जा रहा है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के निर्देशन में जिले की स्वास्थ्य टीम ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुनिश्चित और प्रभावी कार्य

किया NQAS प्रमाणन स्वास्थ्य संस्थानों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, स्वच्छता, मरीजों की सुरक्षा, बेहतर उपचार व्यवस्था प्रशासनिक प्रबंधन के आधार पर दिया जाता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर,

छिपछिपी ने इन सभी मानकों पर खरा उतरते हुए यह प्रतिष्ठित प्रमाणन हासिल किया है। इस प्रमाणन के मिलने से अब इस स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को और अधिक सुरक्षित, भरोसेमंद तथा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। साथ ही, यह प्रमाणन क्षेत्र के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के लिए भी एक प्रेरणा का कार्य करेगा जिससे वे भी गुणवत्ता सुधार की दिशा में प्रयासरत रहेंगे इस सफलता में जिला हल्कर नोडल अधिकारी डॉ. नम्रता चक्रवर्ती, सहायक नोडल अधिकारी अविनाश पाण्डेय एवं सु लक्ष्मी रजक, ब्लॉक NQAS टीम तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर छिपछिपी के समस्त स्टाफ का

महत्वपूर्ण योगदान रहा है सभी के समन्वित प्रयासों और समर्पण ने इस उपलब्धि को संभव बनाया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने इस अवसर पर कहा कि जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से हल्कर प्रमाणन दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग, प्रशिक्षण और संसाधनों के समुचित उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है उन्होंने यह भी कहा कि यह उपलब्धि न केवल जिले के लिए गर्व का विषय है बल्कि यह स्वास्थ्य विभाग की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

## नर्मदापुरम के एसटीआर में फिर बाघ की मौत पूर्व पचमढ़ी के पहाड़ों के बीच मिला बाघ का कंकाल



**मीडिया ऑडिटर, नर्मदापुरम (निप्र)**। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के घने जंगल में पहाड़ों के बीच एक बाघ का कंकाल मिला। कंकाल की खबर से एसटीआर में हड़कंप मच गया रात में एसटीआर की फोर्ड डायरेक्टर राखी नंदा, पचमढ़ी सहायक संचालक संजीव शर्मा, रेंजर समेत तमाम स्टाफ मौके के लिए रवाना हुआ बाघ की मौत से सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए जानकारी के मुताबिक एसटीआर के जंगलों में उदबिलावा का सर्वे चल रहा है। डब्ल्यूसीबी और टाइगर रिजर्व मिलकर यह सर्वे करवा रही। प्रभारी डिप्टी डायरेक्टर डीएफओ गौरव शर्मा ने बताया उदबिलावा सर्वे के लिए रात को

टीम एसटीआर के पूर्व पचमढ़ी के पहाड़ों के बीच में पहुंची थी जहां एक बाघ का कंकाल मिला। डिप्टी डायरेक्टर शर्मा ने कहा जिस जगह बाघ कंकाल मिला वो दो पहाड़ों के बीच खाई वाला क्षेत्र है जहां की भी नहीं जाता है। बाघ की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी। पिछले महीने ही छिंदवाड़ा के सांगखेड़ा रेंज के छत्तीआम में अफीम की खेती के लिए एक बाघ को मारकर गद्दा दिया गया था बाघ एसटीआर का था जिसमें कॉलर आईडी लगी थी छिंदवाड़ा से लगे क्षेत्र में फिर से बाघ का कंकाल मिला ऐसे में जहां बाघ का कंकाल मिला वहां शिकार की आशंका है।

## भागवत कथा में उठा गांव का नाम बदलने का मुद्दा:दाबर अली से दाबर बली करने का संकल्प

**मीडिया ऑडिटर, शिवपुरी (निप्र)**। नवर तहसील के ग्राम दाबर अली में आयोजित भागवत कथा के दौरान गांव का नाम बदलने का मुद्दा उठा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता धैर्यवर्धन ने ग्रामीणों से गांव का नाम दाबर अली से बदलकर दाबर बली करने का आह्वान किया। कथा श्रवण के लिए पहुंचे धैर्यवर्धन का ग्रामीणों ने स्वागत किया अपने संबोधन में उन्होंने यह सुझाव दिया और कथा पंडाल में मौजूद लोगों से हाथ उठाकर समर्थन मांगा जिस पर ग्रामीणों ने संकल्प लिया। व्यास पीठ पर विराजमान आचार्य कृष्णानंद गिरी महाराज ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आशीर्वाद दिया धैर्यवर्धन ने ग्रामीणों से चर्चा में कहा कि गांव में शत-प्रतिशत हिंदू आबादी है और यहां किसी पौर-पैतृक का वंशज नहीं रहता इसलिए वर्तमान नाम उचित नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि भविष्य में इस नाम को लेकर भ्रम



की स्थिति बन सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि दाबर बली नाम रखने से हनुमान जी का आशीर्वाद और शक्ति गांव के साथ जुड़ी रहेगी क्योंकि यहां प्राचीन हनुमान मंदिर और एक सिद्ध कुआं भी मौजूद है। उन्होंने ग्राम सरपंच चंद्रभान सिंह रावत को सुझाव दिया कि कथा समापन के बाद ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करवाकर संबंधित जनप्रतिनिधियों की अनुमति के साथ इसे ब्लॉक और जिला पंचायत में भेजा जाए धैर्यवर्धन ने आश्वासन दिया कि कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में वे सहयोग करेंगे धैर्यवर्धन ने क्षेत्र की

पहचान को रलगाभी बताते हुए कहा कि यहां की मिट्टी ने कई प्रमुख हस्तियां दी हैं उन्होंने डॉ. ए.एल. शर्मा, डॉ. ओपी शर्मा, जसमंत जाटव, रणवीर सिंह रावत और रमेश खटीक जैसी हस्तियों का उल्लेख कर क्षेत्र की विशेषता बताई कार्यक्रम में आसपास के गांव छित्री, कई, बाँसाढ़, आँखू और इंद्रगढ़ से आए श्रद्धालुओं ने भी इस संकल्प पर सहमति जताई इस मौके पर आचार्य कृष्णानंद गिरी महाराज, सरपंच चंद्रभान रावत, कथा यजमान रखा-गजेरा शर्मा, योगेश पटेल और पत्रकार नंदर तिवारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

## 4.22 के पीछे 21.11करोड़ की मूंग खराब होने की आशंका नर्मदापुरम में ढाई माह से वेयरहाउस में बंद सरकारी अनाज नहीं हुआ कीटनाशक का छिड़काव

**मीडिया ऑडिटर,नर्मदापुरम (निप्र)**। एकलव्य एमपी एगो वेयरहाउस गोर में 4.22 करोड़ रुपए की सरकारी मूंग गायब होने का मामला उजागर हुआ था जिस कारण करीब ढाई माह से वेयरहाउस सील है जबकि नियम अनुसार गोदाम में उपज को खराब और कीटों से बचाने के लिए हर 15, 20 दिनों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना अनिवार्य होता है ऐसे गोदाम में रखी करीब 21.11करोड़ रुपए की सरकारी मूंग में कीट लगने और खराब होने की आशंका है वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक वासुदेव डवडे द्वारा कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए माखननगर थाना प्रभारी को तीन बार पत्र भी लिखे 1 अप्रैल को पत्र लिखा जिसे एक माह हो चुका है लेकिन कोर्ट में मामला होने से अबतक गोदाम में रखी



26397 क्विंटल मूंग खराब होने का खतरा है। जिसकी कीमत अनुमानित कीमत करीब 21 करोड़ 11 लाख 80 हजार रुपए है ऐसे में सरकार पत्राचार के चक्कर में 4.22 करोड़ की मूंग ढूँढने के चक्कर में अफसरों ने 21.11करोड़ रुपए की मूंग को दांव पर लगा दिया है माखननगर थाना प्रभारी अनुप कुमार उड्डे से वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के पत्र और चोरी हुई मूंग को खपत का जानने के लिए संपर्क किया लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई वेयरहाउस

कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक वासुदेव डवडे ने 1अप्रैल को माखननगर थाना प्रभारी को पत्र लिखा जिसमें उल्लेख किया कि मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्यालय की शाखा माखननगर अंतर्गत जेन्ही.एस. गोदाम एकलव्य एगो केंद्र पर एण्ड वेयरहाउस 69 ने भण्डारित ग्रीष्मकालीन मूंग (2023-24) की अवैध निकासी के कारण थाना माखननगर अंतर्गत पुलिस प्रतिकूल प्रभाव डालता है जिससे स्कंध में कीटों का संक्रमण प्रारंभ हो जाता है जो कि स्कंध की मात्रा

चूँकि गोदाम में भण्डारित किसी भी स्कंध का समय समय पर स्कंध की सुरक्षा एवं गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उचित कीटोपचार जैसे कीटनाशक औषधि का छिड़काव, धूम्रिकरण (फ्यूमीगेशन कन्वर्) करना एवं नियमित रूप से वायु संचार किया जाना आवश्यक होता है ताकि स्कंध को कीटों से सुरक्षित रखा जा सके एवं भण्डारित स्कंध की गुणवत्ता बनी रहे परंतु एकलव्य वेयरहाउस सीलबंद होने के कारण गोदाम में भण्डारित मूंग का कीटोपचार व नियमित वायुसंचार नहीं होने से स्कंध की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है चूँकि गोदाम बंद रहने पर वेंटिलेशन नहीं होता जिससे अंदर नमी बढ़ जाती है एवं तापमान में वृद्धि होती है जो कि स्कंध की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जिससे स्कंध में कीटों का संक्रमण प्रारंभ हो जाता है जो कि स्कंध की मात्रा

एवं गुणवत्ता के लिये हानिकारक है जिससे शासन को आर्थिक क्षति होने की संभावना है स्कंध की गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए आपके किसी प्रतिनिधि की उपस्थिति में कीटोपचार कराने हेतु गोदाम खुलवाने के लिए अनुरोध है। मप्र वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के कर्मचारी सिमरन ट्रेडिंग कंपनी पिंपरिया के प्रतिनिधि को संपल दिखाने के लिए 13 फरवरी को एकलव्य वेयरहाउस पहुंचे थे गोदाम में रखी बोरिया अस्त व्यस्त पड़ी थी सूचना पर जॉन मैनेजर हेमंत चंदेल खुद गोदाम पहुंचे मूंग चोरी के शक में 14 फरवरी को उन्होंने शिकायत की मामले में मप्र वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन क्षेत्रीय प्रबंधक अतुल सोरटे, जिला प्रबंधक वासुदेव डवडे, तत्कालीन तहसीलदार अंकित मौर्य ने 16 फरवरी को वेयरहाउस का ताला तुड़वाकर मूंग देखी थी।

## नर्मदापुरम में FCI के रिजेक्शन पर भड़के सांसद दर्शन चौधरी 10 ट्रक लौटने पर बोले सब गेहूं सिलेक्ट करो रिजेक्ट नहीं

**मीडिया ऑडिटर, नर्मदापुरम (निप्र)**। सांसद दर्शन सिंह चौधरी शुक्रवार रात करीब 8 बजे अनाज मंडी स्थित गेहूं उपाजिन केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने खरीदी व्यवस्था का निरीक्षण किया और किसानों व कर्मचारियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान रायपुर सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक दीपक थापक और नर्मदांचल विपणन सहकारी संस्था के प्रबंधक जीतू राजपुत ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा बड़ी मात्रा में गेहूं रिजेक्ट किया जा रहा है। इसके चलते नर्मदांचल संस्था के 7 ट्रक और रायपुर सोसायटी के 3 ट्रक एफसीआई गोदाम से वापस लौटा दिए गए जिससे किसानों का भुगतान अटक गया है। इस पर सांसद ने तुरंत जिला पंचायत सीईओ हिमांशु सिंह, नागरिक आपूर्ति निगम के डीएम वासुदेव डवडे, नागरिक



आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक सुरेश मनखेरे को मंडी कार्यालय बुलाकर स्थिति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि गेहूं एफएक्यू (FAQ) मानक का नहीं होने के कारण रिजेक्ट किया गया। सांसद चौधरी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हार्बेस्टर से कटाई में थोड़ी बहुत मिट्टी आना स्वाभाविक है इसे आधार बनाकर गेहूं रिजेक्ट करना उचित नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि साफ-सफाई,

छाई और अन्य उपाय कर गेहूं को मानक के अनुरूप तैयार किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ध्यान रिजेक्शन पर नहीं बल्कि अधिक से अधिक गेहूं को स्वीकार (सेलेक्ट) करने पर होना चाहिए। सांसद ने उपाजिन केंद्र पर किसानों की सुविधाओं को लेकर भी कई निर्देश दिए उन्होंने कहा कि किसानों की संख्या बढ़ाई जाए पीने के पानी छंव और भोजन की बेहतर व्यवस्था हो मच्छरों से बचाव के लिए दवा का छिड़काव किया जाए प्रयास किया जाए कि किसानों को रात में रुकना न पड़े। जिला पंचायत सीईओ हिमांशु सिंह ने वेयरहाउस कॉर्पोरेशन और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों से कहा कि एफसीआई के सर्वेयर को मौके पर बुलाकर गेहूं की जांच कराई जाए ताकि

रिजेक्शन के वैज्ञानिक कारण स्पष्ट हो सकें और अनावश्यक अस्वीकृति से बचा जा सके। निरीक्षण के दौरान सांसद ने किसानों और कर्मचारियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। अनाज मंडी में नर्मदा अंचल विपणन संघ और रायपुर सेवा सहकारी समिति द्वारा गेहूं की खरीदी की जा रही है। खास बात यह है कि दोनों ही केंद्र पर गेहूं की जांच समिति के कर्मचारी ही कर रहे हैं यहां पर सर्वे नियुक्त नहीं किए गए हैं। ऐसे में ऐसे सख्त माल जांचना बड़ा सवाल है। इसी वजह से एफसीआई द्वारा दोनों ही केंद्र के गेहूं को नर्मदा लौटाया जा रहा है। गेहूं रिजेक्ट होने के कारण किसानों का भुगतान अटक गया है। नियम अनुसार किस को सा दिन के अंदर भुगतान होना था लेकिन रिजेक्ट वहां परिसर नहीं होने के कारण 20 दिन बाद भी किसानों को भुगतान नहीं हो पाया।

## क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता में पीएमस्कूल का दबदबा शिवपुरी के छात्रों ने स्केटिंग में जीते 9 स्वर्ण

**मीडिया ऑडिटर, शिवपुरी (निप्र)**। भोपाल क्षेत्र में आयोजित 55वीं क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता में केन्द्रीय विद्यालय आईटीबीपी शिवपुरी के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। छात्रों ने स्केटिंग, वॉलीबॉल, शतरंज, शूटिंग और जूडो सहित विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट खेल दिखाते हुए कई पदक अपने नाम किए हैं। विजेता खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्राचार्य और समस्त स्टाफ ने उन्हें बधाई देते हुए उज्वल भविष्य की कामना की है। प्रतियोगिता के स्केटिंग इवेंट में विद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन-सबसे उल्लेखनीय रहा। अंडर-17 वर्ग में चित्राश दोहरे ने सर्वाधिक 3 स्वर्ण पदक जीते। इसी वर्ग में आदित्य मिश्रा



ने 1 स्वर्ण और 2 रजत, अर्जित धाकड़ ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य, पीयूष राठौर ने 1 स्वर्ण, आर्यन यादव ने 2 स्वर्ण तथा ईशान नामदेव ने 2 रजत पदक प्राप्त किए। अंडर-14 वर्ग में अर्नव गुप्ता ने 1 स्वर्ण और अभिनव सिंह जाट ने 1 रजत पदक हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। टीम इवेंट की बात करें तो अंडर-17 बालक वर्ग की वॉलीबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता है जबकि अंडर-17 बालिका टीम चौथे स्थान पर

रही व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में रुद्र वास्तव ने कांस्य पदक प्राप्त किया शतरंज प्रतियोगिता के अंडर-17 वर्ग में हर्ष माथुर ने कांस्य और अंडर-14 वर्ग में लावण्या सेन ने रजत पदक हासिल किया खेल प्रतियोगिता का आयोजन 28, 29 और 30 अप्रैल तक भोपाल के अलग-अलग केंद्रीय विद्यालयों में चला था अन्य व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी विद्यार्थियों ने सफलता दर्ज की है।

## नाती ने रची थी दादी की हत्या की साजिश,सुपारी लेकर आए दोस्त ने पैर छूकर मार दी थी गोली



**मीडिया ऑडिटर, शिवपुरी (निप्र)**। तेंदुआ थाना क्षेत्र के डेहरवा गांव में 22 अप्रैल को हुई बुजुर्ग महिला रामसखी धाकड़ की हत्या का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार इस वारदात का मास्टरमाइंड महिला का नाती निकला जिसने अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। घटना 22 अप्रैल की दोपहर की है जब तीन युवक बाइक पर सवार होकर डेहरवा गांव पहुंचे। उन्होंने शायी का कार्ड देने के बहाने रामसखी धाकड़ के

घर का दरवाजा खुलवाया जैसे ही महिला बाहर आई एक युवक ने पहले उनके पैर छूए और फिर तुरंत उनके सिर में गोली मार दी यह वारदात नातिन के सामने हुई थी। जांच में सामने आया कि रामसखी धाकड़ की शादी लक्ष्मी नारायण लोधी से हुई थी। परिवार के पास करीब 35 बीघा जमीन थी जिसका बंटवारा पहले ही हो चुका था रामसखी अपनी हिस्से की जमीन अपने बेटे मुनेश धाकड़ के नाम करना चाहती थीं जिससे परिवार में विवाद बढ़ गया था शुरुआत में शक सौतेले बेटों पर

गया था जिन पर नामांतरण का विरोध करने का आरोप था। एसडीओपी संजय मिश्रा ने बताया कि पुलिस जांच के बाद इस हत्या का मास्टरमाइंड रामसखी की सौतेली बेटे गुड्डू धाकड़ का बेटा पुष्पराज धाकड़ निकला पुलिस के मुताबिक पुष्पराज अपनी मां के साथ रामसखी द्वारा कथित दुर्व्यवहार से नाराज था और इसी का बदला लेने के लिए उसने हत्या की योजना बनाई। पुष्पराज की दोस्ती शिवपुरी में रहने वाले निकेंद्र रावत से थी जो कर्ज में डूबा हुआ था पुष्पराज ने निकेंद्र को पैसे का लालच देकर हत्या के लिए राजी किया हत्या के दिन दोनों शायी का कार्ड लेकर घर पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल निकेंद्र की थी और गोली भी उसी ने चलाई थी।

## महिला समूह के खरीदी केंद्र की हकीकत पुरुष कर रहे संचालन देरी से तुलाई महिला सशक्तिकरण का मकसद फेल

**मीडिया ऑडिटर, नर्मदापुरम (निप्र)**। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से स्व-सहायता समूहों को गेहूं खरीदी केंद्रों का संचालन सौंपा गया है लेकिन जिले में इसकी जमीनी हकीकत अलग नजर आ रही है कई केंद्रों पर महिलाओं की जगह पुरुष ही पूरा काम संभाल रहे हैं जिससे शासन के उद्देश्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला मुख्यालय से करीब 6 किमी दूर जासलपुर स्थित किसान वेयरहाउस में जमुना स्व-सहायता महिला समूह को खरीदी की जिम्मेदारी दी गई है शनिवार सुबह 10:15 बजे मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि केंद्र पर न तो प्रभारी सुनीता चौरे मौजूद थीं और न ही समूह की कोई सदस्य। वहीं



पुरुष कर्मचारी ही गेहूं की जांच और तुलाई करते नजर आए कि केंद्र पर गेहूं से भरी करीब 35 ट्रालियां कतार में खड़ी थीं। किसान खरीदी शुरू होने का

इंतजार करते रहे लेकिन समय पर तुलाई शुरू नहीं हो सकी बाद में अचानक ट्रालियों को अंदर बुलाकर तुलाई शुरू करने की प्रक्रिया दिखाई गई।

पुरुषों द्वारा ही पूरी खरीदी प्रक्रिया संचालित की जाती रही कलेक्टर के निर्देश के बावजूद देरी से शुरू हो रही खरीदी गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने सुबह जल्दी तुलाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं लेकिन यहां खरीदी देरी से शुरू हो रही है वेयरहाउस संचालक अमर सिंह ने देरी का कारण परिवहन कार्य बताया जबकि मौके की स्थिति कुछ और ही दर्शाती है। जिला मुख्यालय के पास ही यह स्थिति होने से अन्य केंद्रों की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य कमजोर पड़ता दिख रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों की मॉनिटरिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

वेयरहाउस संचालक ने बताया कि महिलाएं 11 बजे तक आएंगी लेकिन तय समय तक कोई भी महिला कर्मचारी केंद्र पर नहीं पहुंची इसके बावजूद



# थॉमस कप: फ्रांस पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा, भारत से होगा मुकाबला

होर्संस, एजेंसी। डेनमार्क के फोर्म होर्संस में खेले जा रहे थॉमस कप में फ्रांस ने इतिहास रचा है। फ्रांस ने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। फ्रांस ने जापान पर 3-0 की शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई। डेनमार्क ने भी अंतिम चार में अपनी जगह बना ली है। फ्रांस की टीम ने टूर्नामेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जिसमें पूरी तरह से एकल में सफलता मिली। बीच-बीच में कड़ी टकराव मिलने के बावजूद, क्रिस्टो पोपोव, एलेक्स लैनियर और टोमा जूनियर पोपोव, दोनों ने सीधे गेम में अच्छे प्रदर्शन किया और बिना डबल्स की जरूरत के मैच अपने नाम कर लिया। क्रिस्टो ने कोडर्ड नाराओका के खिलाफ एक मुश्किल शुरुआती मुकाबले में लय बनाई और आखिरकार जीत हासिल की।

बिडब्ल्यूएफ ने क्रिस्टो के हवाले से कहा, जब आप कोडर्ड के साथ खेलते हैं, तो आपको पता होता है कि यह लंबा होने वाला



है और आप जानते हैं कि वह आसान गलतियां नहीं करेगा। वह आपको दौड़ाएगा, आपको

बहुत पसीना दिलाएगा। वह इसमें बहुत अच्छा है। मैं इसके लिए तैयार था।

इसके बाद लैनियर ने युशी तानाका पर जीत के साथ फ्रांस की बढ़त को बढ़ाया, जिससे

टीम एक ऐतिहासिक नतीजे की कगार पर पहुंच गई। निर्णायक तीसरे रबर में टोमा जूनियर पोपोव ने कोकी वतनबे के खिलाफ 21-19, 23-21 से जीत हासिल की।

टोमा जूनियर ने कहा, मैं बहुत खुश और आनंदित हूँ। मेरे शरीर में अब ऊर्जा नहीं बची है। मैंने कोर्ट पर अपना सब कुछ ड्रॉक दिया। यह बस अविश्वसनीय है। हमने मंगलवार को इंडोनेशिया के खिलाफ जीतकर और क्वालिफाई करके इतिहास रचा, और अब हम इसे फिर से लिख रहे हैं, टीम चैंपियनशिप में पहला मेडल। मुझे लगता है कि हमने फ्रेंच बैडमिंटन फेडरेशन और खुद फ्रांस पर बैडमिंटन के लिए एक बड़ी छाप छोड़ी है। हम आ रहे हैं। हम लड़ने के लिए तैयार हैं।

इस जीत ने न केवल फ्रांस को प्रतिযোগिता में पहला पदक दिलाया, बल्कि भारत के साथ सेमीफाइनल मुकाबला भी तय किया। भारत ने चीनी तापे पर 3-0 से जीत हासिल करके सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है।

भारत की बढ़त लक्ष्य सेन, आयुष शेठी और सत्विकसाईराज रंकीरडू और चिराग शेठी की डबल्स जोड़ी के दमदार प्रदर्शन से मिली। दोनों ने क्वार्टर फाइनल में शानदार नतीजे में योगदान दिया।

डेनमार्क ने थाईलैंड पर 3-1 से जीत हासिल करके मेजबान टीम को मुकाबले में बनाए रखा। एंडर्स एंटोनसेन ने तीन गेम के मुकाबले में कुनलालुत विटिड्डमान को हराया, जिसके बाद किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारप रासमुसेन ने डबल्स में दूसरा पॉइंट जोड़ा।

थाईलैंड ने पैनिचाफान तीरात्साकुल के जरिए थोड़ी देर के लिए वापसी की कोशिश की, जिन्होंने मैग्स जोहानसेन को हराया, लेकिन डेनमार्क की मैथियास क्रिस्टियनसेन और डेनियल लुंडगार्ड की जोड़ी ने सीधे गेम में टाई पकड़ कर दिया। चीन के भी आगे बढ़ने के साथ, सेमीफाइनल में अब पारंपरिक पावरहाउस और उभरते हुए दावेदारों का जबरदस्त मिश्रण होने की उम्मीद है।



## रोड्स, फाफ डु प्लेसी और हेनरिक क्लासेन अब बने टीम मालिक

जोहांसबर्ग, एजेंसी। दक्षिण अफ्रीका के तीन पूर्व क्रिकेटर्स जोटी रोड्स, फाफ डु प्लेसी और हेनरिक क्लासेन ने मिलकर एक टीम खरीदी है और अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया है। अब गुजरे जमाने के ये दिग्गज यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग में रोटरडम फ्रैंचाइजी के मालिक बन गये हैं। यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) से जो यूरोप में क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव का अंदाजा होता है। यह कदम यूरोपीय महाद्वीप में टी20 क्रिकेट के विस्तार और व्यावसायिक संभावनाओं को दिखाता है।

यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग का पहला सत्र 26 अगस्त से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में शहर-आधारित फ्रैंचाइजी होंगी, जिसका उद्देश्य स्थानीय प्रशंसकों को खेल से जोड़ना और यूरोप के विभिन्न हिस्सों में क्रिकेट के प्रति उत्साह पैदा करना है। रोटरडम के अलावा, लीग में अन्य शहर-आधारित फ्रैंचाइजी में ग्लासगो, एम्सटरडम, एडिनबर्ग, डबलिन और बेलफास्ट शामिल हैं। यह संरचना विभिन्न यूरोपीय शहरों को क्रिकेट से जोड़ने और स्थानीय प्रशंसकों में उत्साह पैदा करने का लक्ष्य रखती है।

गौरतलब है कि रोड्स, अपनी शानदार फील्डिंग के लिए विश्व-प्रसिद्ध, खेल में हमेशा याद किये जाते हैं। उनका अनुभव और खेल की गहरी समझ निश्चित रूप से रोटरडम टीम को रणनीति बनाने और युवा प्रतिभाओं को निखारने में मदद करेगी। वहीं फाफ डु प्लेसी, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान और एक अनुभवी टी20 लीग खिलाड़ी, की कप्तानी और बल्लेबाजी कोशल ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई है। उनका यह कदम मालिक के रूप में क्रिकेट इकोसिस्टम में प्रवेश करने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। हेनरिक क्लासेन, एक विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज, आधुनिक टी20 क्रिकेट की मांगों को भली-भांति समझते हैं और उनकी गेम-चेजिंग क्षमता टीम के लिए बहुमूल्य होगी। इन तीनों का संयोजन न केवल टीम को मजबूती देगा, बल्कि लीग की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक विश्वसनीयता प्रदान करेगा।

पिछले कुछ वर्षों में, टी20 लीगों का उदय खेल के व्यावसायिक परिदृश्य को बदल रहा है, जिसमें खिलाड़ी अब केवल मैदान पर प्रदर्शन करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे खेल के प्रशासनिक और व्यावसायिक पहलुओं में भी अपनी जगह बना रहे हैं। यह कदम यूरोप में क्रिकेट के लिए एक गेम-चेजर साबित हो सकता है, जहां पारंपरिक रूप से यह खेल उतना लोकप्रिय नहीं रहा है जितना कि दक्षिण एशिया या ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में है पर अब इन दिग्गजों के आने से हालात बदलना तय है।

## फॉर्मूला 1-मैकलारेन के लैंडो नॉरिस का शानदार प्रदर्शन

स्प्रिंट रेस के लिए पोल पोजीशन अपने नाम की

मियामी, एजेंसी। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप के मियामी ग्रांड प्रिक्स वीकेंड की शुरुआत बेहद रोमांचक रही। मैकलारेन के लैंडो नॉरिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्प्रिंट रेस के लिए पोल पोजीशन अपने नाम कर ली। नॉरिस ने एक बेहतरीन लैप लगाकर मर्सिडीज के युवा और इन-फॉर्म ड्राइवर किमी एंटेनेली को पीछे छोड़ते हुए टीम को अहम बढ़त दिलाई। नॉरिस ने 1:27.869 का तेज लैप टाइम निकाला, जो पूरे सेशन में सबसे बेहतर साबित हुआ। हाई रैंक स्टेडियम सर्किट पर उनकी समझ और कार पर पकड़ साफ नजर आई। उन्होंने एंटेनेली को 0.222 सेकंड के अंतर से पछड़कर पोल पोजीशन हासिल की। इस उपलब्धि के बाद नॉरिस काफी खुश नजर आए। नॉरिस ने कहा कि टीम ने कार में कई नए बदलाव किए हैं, जिनका सकारात्मक असर दिखा है। जीत टीम के इंजीनियरों और मैकेनिकों की मेहनत का इनाम है। कार में बेहतर ग्रिप मिलने से उन्हें ट्रैक पर आत्मविश्वास मिला।



क्वालिफाइंग में एंटेनेली दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मैकलारेन के ही ऑस्कर पिआस्ट्री तीसरे स्थान पर क्वालिफाई करने में सफल रहे। फेरारी के चार्ल्स लेक्लेर्क चौथे स्थान पर रहे। रविवार को होने वाली मुख्य रेस से पहले शनिवार की 100 किलोमीटर की स्प्रिंट रेस बेहद अहम होगी।

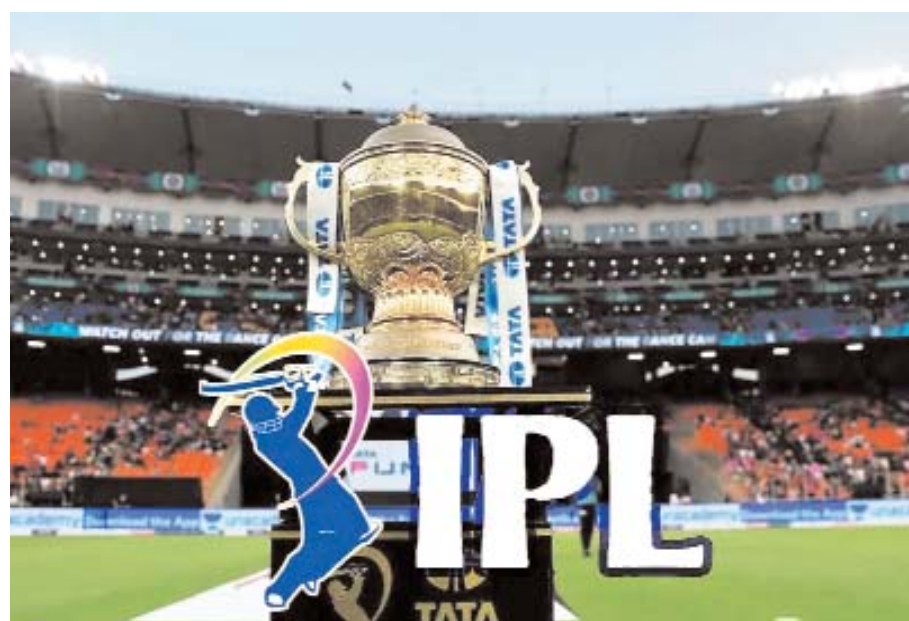
पिछले साल मियामी में स्प्रिंट जीतने वाले नॉरिस ने इस ट्रैक के प्रति अपना लगाव जताते हुए कहा कि उन्हें मियामी ट्रैक के साथ-साथ यहां का माहौल भी बेहद पसंद है। वीकेंड अभी लंबा है और असली चुनौती अभी बाकी है।

रेड बुल के चार बार के वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन इस बार पांचवें स्थान पर रहे। यह उनके लिए निराशाजनक रहा। मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल छठे स्थान पर रहे। रसेल ने मैकलारेन और फेरारी की तेजी पर हैरानी जताई और माना कि दोनों टीमों ने जबरदस्त सुधार किया है। रसेल ने अपनी परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि मियामी ट्रैक उनके लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, खासकर गर्म मौसम में। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्प्रिंट रेस में वे बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। टॉप 10 में आइजैक हैडजर और पिपेर गैस्ली भी शामिल रहे। वहीं, एप्टन मार्टिन के लिए यह सेशन निराशाजनक रहा, जहां फर्नांडो अलेंसो और लांस स्ट्रोल ग्रिड के सबसे पीछे रहे। यहां तक कि वे नई टीम कैडिलैक से भी पीछे रह गए। मियामी ग्रां प्री का आगाज दिलचस्प रहा है। स्प्रिंट रेस के साथ-साथ मुख्य रेस में भी कड़ी टकराव होने की उम्मीद है।

## दिल्ली कैपिटल्स की ऐतिहासिक चेज़, पॉइंट्स टेबल में मिली बड़ी छलांग

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली कैपिटल्स को आखिरकार तीन हार के बाद एक बहुप्रतीक्षित जीत नसीब हुई है। शुरुआत को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसने न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया बल्कि उन्हें आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में भी जबरदस्त फायदा पहुंचाया। दिल्ली की इस शानदार जीत में केएल राहुल और पथुम निसांका का अहम रोल रहा।

राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रियान पराग की 90 रनों की शानदार कप्तानी पारी के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 225 रन का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगाया। इस चुनौतीपूर्ण स्कोर का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम के



लिए केएल राहुल ने 40 गेंदों पर 75 रनों की धुआंधार पारी खेली।

उन्हे सलामी जोड़ीदार पथुम निसांका ने भी सिर्फ 33 गेंदों पर

62 रन बनाकर राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 110 रनों की

मजबूत साझेदारी की, जिसने जीत की नींव रखी। दिल्ली ने यह विशाल लक्ष्य 5 गेंदों और 7 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया, जो दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल के इतिहास में अभी तक चेज़ किया गया सबसे बड़ा टारगेट था।

दिल्ली की टीम को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इस जीत से आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त फायदा मिला है। दिल्ली कैपिटल्स 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को पछड़कर 6ठे पायदान पर पहुंच गई है। दिल्ली की यह 9 मैचों में चौथी जीत है, और उनके खाते में अब कुल 8 अंक हो गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के अलावा पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के भी 8 अंक हैं, जिससे मध्य क्रम में प्लेऑफ की

दौड़ और भी रोमांचक हो गई है। दूसरी ओर, रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 7 विकेट से करारी हार झेलने के बावजूद शीर्ष-4 में बरकरार है। राजस्थान रॉयल्स की यह 10 मैचों में चौथी हार है, लेकिन राजस्थान इससे पहले 6 मैच जीत चुकी थी, जिससे उनके खाते में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बराबर 12-12 अंक हैं। यह हार राजस्थान के लिए एक झटका जरूर है, लेकिन वे अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। दिल्ली के लिए यह जीत प्लेऑफ की उम्मीदों को ज्वाला रखने वाली साबित हुई है, और अब उन्हें आने वाले मैचों में इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखना होगा ताकि वे शीर्ष-4 में जगह बना सकें।

## गोल्फ: एमसीबी लेडीज क्लासिक के पहले दिन दीक्षा की शानदार शुरुआत

पोर्ट लुइस, एजेंसी। मॉरीशस में पहली बार खेले जा रहे एमसीबी लेडीज क्लासिक के पहले दिन भारत की दीक्षा डागर ने होल-इन-वन लगाकर जोरदार शुरुआत की नींव रखी। आत्मविश्वास से भरे प्रदर्शन ने उन्हें शुरुआती दावेदारों में ला खड़ा किया है। दीक्षा ने कॉन्स्टेंट बेले मारे प्लाज में पहले राउंड में 4-अंडर 68 का मजबूत स्कोर बनाया, जिससे वह संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर पहुंच गईं। अपने राउंड की शुरुआत बैंक नाइन से करते हुए, उन्होंने बिना समय गंवाए अपना अंशर दिखाया और पार-3 वाले 11वें होल पर एक शानदार ऐस (होल-इन-वन) लगा दिया। इसके बाद उन्होंने 15वें और 18वें होल पर बर्डी बनाकर अपना स्कोर 4-अंडर तक पहुंचा दिया। बाद में पांचवें होल पर एक बोगी लगने के बावजूद, उन्होंने नौवें होल पर एक और बर्डी लगाकर शानदार वापसी करते हुए मजबूती से अपना राउंड खत्म किया। अन्य भारतीय खिलाड़ियों में, त्वेसा मलिक ने 2-अंडर 70 का स्थिर स्कोर बनाया और संयुक्त रूप से 20वें स्थान पर रहीं। उनके राउंड में फ्रंट नाइन पर तीन बर्डी शामिल थीं। हालांकि, नौवें होल पर एक डबल बोगी ने उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी। उन्होंने बैंक नाइन पर 15वें और 17वें होल पर



और बर्डी बनाकर फिर से अपनी लय हासिल कर ली।

हिताशी बच्छी ने 1-अंडर 71 के स्कोर के साथ अपना राउंड खत्म किया, जिससे वह संयुक्त रूप से 30वें स्थान पर रहीं, जबकि वाणी

कपूर का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और उन्होंने 78 का स्कोर बनाया। अब उनके लिए कट में जगह बनाना एक मुश्किल चुनौती होगी। दीक्षा और त्वेसा के नेतृत्व में भारतीय खिलाड़ियों की नजरें इस साल के आखिर में होने वाले अपने घरेलू टूर्नामेंट, इंडियन ओपन पर टिकी हुई हैं।

लीडरबोर्ड में सबसे ऊपर, फ्रांस की अगाथे लैसने ने 8-अंडर 64 का जोरदार प्रदर्शन करते हुए पहले दिन ही बढ़त बना ली। उन्होंने जबरदस्त निरंतरता दिखाते हुए 10 बर्डी बनाई और इस सीजन में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा। उनके ठीक पीछे साउथ अफ्रीका की कारा गोरले हैं, जिन्होंने 7-अंडर 65 का स्कोर बनाया, जिसमें दो इंगल भी शामिल थीं। डेनमार्क की स्मिता टार्निंग सोडरबी 6-अंडर 66 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

दीक्षा सहित कई खिलाड़ियों के 4-अंडर पर बराबरी पर होने के कारण, दूसरे राउंड में जाते हुए मुकाबला काफी कड़ा बना हुआ है। अगला चरण जल्दी शुरू होगा, जिसमें केवल शीर्ष 60 खिलाड़ी और बराबरी पर रहने वाले खिलाड़ी ही कट से आगे बढ़ेंगे, जिससे आने वाले दिनों में एक जोरदार मुकाबले का मंच तैयार हो जाएगा।

## एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियों में लगी हैं मनु

नई दिल्ली, एजेंसी। ओलंपिक पदक विजेता महिला निशानेबाज मनु आजकल एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियों में लगी हैं। मनु का लक्ष्य इन टूर्नामेंटों में बेहतर प्रदर्शन कर पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन चक्र के लिए अपनी दावेदारी पकड़ी करना है। मनु का कहना है कि अभी उनका ध्यान अपना फॉर्म बनाये रखते हुए बेहतर प्रदर्शन करने पर है।

मनु ने दृढ़ता से कहा, इस साल एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स हमारे सामने हैं, और हम इन दोनों बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कोच के साथ बैल्के की हैं और आगामी टूर्नामेंट्स तथा अपनी तैयारी की एक संपूर्ण और सुनियोजित रूपरेखा तैयार कर ली है। इससे ये साफ है कि उनकी रणनीति केवल तात्कालिक सफलता पर नहीं, बल्कि एक लंबी अवधि की योजना का हिस्सा है।



उन्होंने पिछले साल 10 मीटर एयर पिस्टल में वर्ल्ड कप रजत पदक जीता और इस साल भी 25 मीटर पिस्टल में एशियन चैंपियनशिप में रजत हासिल किया। अब उनका लक्ष्य एक बार फिर अपनी पुरानी, शीर्ष स्तरीय लय हासिल करना है, जो उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक निर्विवाद मजबूत दावेदार बनाएगी। यह वापसी केवल उनके लिए नहीं, बल्कि भारतीय शूटिंग जात के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होगी।

2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक

का क्वालिफिकेशन चक्र भी इसी साल से शुरू हो रहा है, और मनु भाकर इस पर भी अपनी पैनी निगाहें जमाए हुए हैं। उनका मानना है कि एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजनों में किया गया दमदार प्रदर्शन न केवल उन्हें वर्तमान सत्र में सफलता दिलाएगा, बल्कि लॉस एंजेलिस ओलंपिक के लिए भी एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करेगा।

खेल के साथ अपने व्यक्तिगत जुड़ाव को भी मनु ने साझा किया। उन्होंने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग की वापसी पर अपनी खुशी व्यक्त की। अपने खेल जीवन के अलावा, मनु ने अपने व्यक्तिगत जीवन में आगे एक महत्वपूर्ण बदलाव का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया, मैं अब एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ।

यह आध्यात्मिक यात्रा ओलंपिक के दौरान ही शुरू हुई थी, और अब मैं पूरी तरह से इस रास्ते पर आगे बढ़ रही हूँ। यह नया दृष्टिकोण उन्हें मानसिक शांति और एकग्रता प्रदान कर रहा है, जो एक उच्च-स्तरीय एथलीट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

# जिले में धूमधाम से मनाया गया लाड़ली उत्सव 2026

मीडिया ऑडिटर, मैहर (निप्र)। कलेक्टर विदिशा मुखर्जी के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शनिवार को जिले भर में लाड़ली उत्सव 2026 का आयोजन धूमधाम और उत्साह के साथ किया गया यह जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय पर्यटक सूचना केंद्र में आयोजित किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य जयंती महेश तिवारी ने भाग लिया जबकि नगर पालिका अध्यक्ष गीता संतोष सोनी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की सांसद प्रतिनिधि संतोष सोनी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदा के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ इसके बाद अतिथियों का स्वागत कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई मुख्य अतिथि जयंती महेश तिवारी ने



अपने संबोधन में कहा कि समाज में महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव आया है, लेकिन अभी और प्रगति की आवश्यकता है। उन्होंने उपस्थित जनों से कार्यक्रम के उद्देश्य और संदेश को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का आह्वान किया सांसद प्रतिनिधि संतोष सोनी ने सरकार द्वारा महिला

सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है उन्होंने विशेष रूप से लाड़ली लक्ष्मी योजना की महत्ता पर बल दिया जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज में महिलाओं के

प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र बांगरे ने 'लाड़ली लक्ष्मी योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह योजना बाल विवाह को हतोत्साहित कर एक स्वस्थ समाज की नींव को मजबूत करने में सहायक सिद्ध



हो रही है इस उत्सव के दौरान जिले के अमरपाटन रामनगर सहित सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में भी आयोजन किए गए जहां लाड़ली बालिकाओं ने नृत्य गीत वाद-विवाद और किंवदंती प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन सुप्रिया सेन ने किया कार्यक्रम

के अंत में सभी लाड़ली बालिकाओं को पुष्पगुच्छ एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया इस अवसर पर परियोजना अधिकारी विद्याचरण तिवारी महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बालिकाएं और उनके अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

## सामूहिक दुष्कर्म मामले में फरार दूसरा आरोपी गिरफ्तार



मीडिया ऑडिटर, सतना (निप्र)। जिले के सभापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पगार कला ग्राम में मूकबधिर युवती से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है आरोपी आनंद उर्फ अभय नंद द्विवेदी (23 वर्ष), निवासी मारवा थाना कोटर, घटना के बाद से लगातार फरार था। पुलिस ने उसे पकड़कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है पुलिस टीम की सक्रियता से मिली सफलता मामले की गंभीरता को देखते हुए सभापुर

थाना पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। थाना प्रभारी शंखधर द्विवेदी के नेतृत्व में गति टीम ने सूझबूझ और तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। इस अभियान में उपनिरीक्षक अशोक गर्ग, आरक्षक अमोद शर्मा और सैनिक अंकित शुक्ला की महत्वपूर्ण भूमिका रही पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच जारी है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सभी आवश्यक कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में कानून व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है।

## प्रदूषणकारी फैक्ट्री के पास अवैध कॉलोनी निर्माण, नियमों की अनदेखी पर उठे सवाल

मीडिया ऑडिटर, सतना (निप्र)। नगर परिषद क्षेत्र जैतवारा में एक ओर जहां प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री संचालित हो रही है वहीं उसके समीप अवैध कॉलोनी निर्माण का मामला सामने आने से प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं स्थानीय लोगों के अनुसार कथित रूप से मदन अग्रवाल द्वारा बंजर भूमि पर पहले गेरू, रामराज एवं केमिकल की बड़ी फैक्ट्री स्थापित की गई जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण का असर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री के प्रभाव से नगर परिषद के अधिकारी-कर्मचारी भी अछूते नहीं हैं आरोप है कि इसी भूमि के शेष हिस्से में बिना आवश्यक अनुमति और नियमों का पालन



किए कॉलोनी विकसित कर भूखंड बेचे जा रहे हैं। 20-20 फीट चौड़ी सड़कों, नाली, पानी, बिजली और पार्क जैसी सुविधाओं का दावा कर लोगों को आकर्षित किया गया जबकि जमीनी स्तर पर इन सुविधाओं की स्थिति संदिग्ध बताई जा रही है सूत्रों के मुताबिक इस कॉलोनी के लिए न तो संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिया गया है और न ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से स्वीकृति

प्राप्त की गई है। इसके अलावा, परियोजना का पंजीकरण रेरा (RERA) में भी नहीं कराया गया है जो कि किसी भी वैध कॉलोनी विकास के लिए अनिवार्य माना जाता है इस मामले को लेकर नगर परिषद के कुछ जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो यह मामला और गंभीर हो सकता है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण



को उच्च न्यायालय तक ले जाने की बात भी कही है विशेषज्ञों का मानना है कि बिना वैध दस्तावेजों के खरीदे गए भूखंड भविष्य में कानूनी विवादों में फंस सकते हैं और रजिस्ट्रारों भी शून्य घोषित हो सकते हैं ऐसे में संभावित खरीदारों को सतर्क रहने की आवश्यकता है अब देखा होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और नियमों के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई करता है।

## क्रिकेट सट्टेबाजी पर उठे सवाल, कार्रवाई पर संदेह

मीडिया ऑडिटर, सतना (निप्र)। देश के कई शहरों में क्रिकेट सट्टेबाजी के बड़े मामलों का खुलासा होने के बावजूद सतना जिले में इस तरह की गतिविधियों पर ठोस कार्रवाई न होने से सवाल उठने लगे हैं हाल ही में दिल्ली में लगभग 100 करोड़ रुपये के क्रिकेट सट्टे का भंडाफोड़ हुआ, वहीं बैतूल, जबलपुर, कटनी और रीवा जैसे शहरों में भी नगदी, लैपटॉप और मोबाइल के साथ सट्टेबाजों की गिरफ्तारी हुई है इसके विपरीत सतना में लंबे समय से सट्टेबाजी की चर्चाएं होने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं लगना चर्चा का विषय बना हुआ है सूत्रों के अनुसार, सतना जिले में क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़े कई कथित सफेदपोशों के नाम सामने आ रहे हैं आरोप यह भी लगा रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण और प्रभाव के चलते इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वहीं कुछ

लोग पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या अवैध वसूली या दबाव के कारण इस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है इन दिनों आईपीएल के चलते सट्टेबाजी का बाजार अपने चरम पर है जिसमें करोड़ों रुपये का लेन-देन हो रहा है सट्टा कारोबार से जुड़े जानकारों का दावा है कि सतना में भी बड़े स्तर पर सट्टा संचालित हो रहा है और इसकी लाइन आसानी से उपलब्ध हो जाती है ऐसे में सवाल उठता है कि जब यह जानकारी आम लोगों तक पहुंच रही है तो पुलिस इससे अनजान कैसे रह सकती है हालांकि इस पूरे मामले में आधिकारिक रूप से पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है अब देखा होगा कि आगामी समय में प्रशासन इस दिशा में क्या कदम उठाता है। फिलहाल जिले में सट्टेबाजी को लेकर चर्चाएं तेज हैं और लोग निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।

## स्वच्छ वार्ड रैंकिंग अभियान शुरू, 24 वार्डों में होगी प्रतिस्पर्धा

मीडिया ऑडिटर, सतना (निप्र)। नगर पालिका परिषद मैहर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत स्वच्छ वार्ड रैंकिंग अभियान की शुरुआत कर दी गई है इस अभियान के जरिए शहर के सभी 24 वार्डों में स्वच्छता को लेकर प्रतिस्पर्धा कराई जाएगी ताकि मेहर को साफ-सुथरा और सुंदर बनाया जा सके नगर पालिका के अनुसार वार्डों और कॉलोनीयों के निवासी अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखकर रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अभियान में कचरा प्रबंधन प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र डोर-टू-डोर क्लेक्शन गीला-सूखा कचरा पृथक्करण और स्वच्छ शौचालय जैसे मानकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान 01 अप्रैल से 25 मई 2026 तक चलेगा। इसके बाद 26 मई से 30 मई तक आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। रैंकिंग के परिणाम और सम्मान वितरण 5 जून 2026 को

किया जाएगा नगर पालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वे बड़े-चढ़कर इस अभियान में भाग लें और अपने वार्ड को नंबर वन बनाने में योगदान दें। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए नोडल अधिकारी प्रवीण तिवारी मोबाइल नंबर 9617929579 से सम्पर्क करने की व्यवस्था की गई है विश्व पर्यावरण दिवस पर 'स्वच्छ वार्ड रैंकिंग' विजेताओं का होगा सम्मान नगर पालिका कॉलोनीयों के निवासी अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखकर रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अभियान में कचरा प्रबंधन प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र डोर-टू-डोर क्लेक्शन गीला-सूखा कचरा पृथक्करण और स्वच्छ शौचालय जैसे मानकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान 01 अप्रैल से 25 मई 2026 तक चलेगा। इसके बाद 26 मई से 30 मई तक आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। रैंकिंग के परिणाम और सम्मान वितरण 5 जून 2026 को

## मां शारदा धाम रोपवे क्षेत्र में दलालों का बढ़ता असर, श्रद्धालु परेशान

मीडिया ऑडिटर, मैहर (निप्र)। धार्मिक नगरी मैहर स्थित मां शारदा धाम के रोपवे परिषद क्षेत्र में दलालों की बढ़ती सक्रियता को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व रोपवे परिसर के आसपास सक्रिय होकर बाहर से आने वाले भक्तों को गुमराह कर रहे हैं ये दलाल टिकटिंग और दर्शन व्यवस्था के नाम पर अनावश्यक सुविधा बताकर अवैध वसूली करते हैं। जानकारी के अभाव में कई श्रद्धालु इनके झांसे में आ जाते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ती है इस स्थिति से धार्मिक स्थल को छवि भी प्रभावित हो रही है।

प्रशासन से जांच की मांग: स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि बिना रोपवे कर्मचारियों की मिलीभगत के इस प्रकार की गतिविधियां लगातार चल पाना संभव नहीं है यही कारण है कि अब इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो समस्या और गंभीर हो सकती है उन्होंने जिला प्रशासन से पूरे रोपवे परिसर की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों एवं दलालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कलेक्टर से तत्काल हस्तक्षेप कर पारदर्शी व्यवस्था और सख्त निगरानी सुनिश्चित करने की अपील की गई है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन का लाभ मिल सके।

## गोपालपुर में कागजों पर टैंकर मरम्मत, जमीनी हकीकत में धंसी व्यवस्था

मीडिया ऑडिटर, सतना (निप्र)। भीषण गर्मी के बीच जहां तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और जलस्तर 300 फीट नीचे चला गया है, वहीं मझगवां ब्लॉक की ग्राम पंचायत गोपालपुर में पेयजल व्यवस्था को लेकर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। गांव के लोग बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पंचायत के रिकॉर्ड में टैंकर मरम्मत के नाम पर हजारों रुपये खर्च दिखाए जा रहे हैं जानकारी के अनुसार पंचायत के दो टैंकरों में से एक का कोई पता नहीं है, जबकि दूसरा टैंकर जर्जर हालत में जमीन में रिम तक धंसा हुआ है। इसके बावजूद 6 मार्च 2026 को 'विराट ट्रेडर्स' के नाम पर 738,300 के दो बिल लगाकर भुगतान किया गया। हैरानी की बात यह है कि बिल में दर्ज



के.बी.के. रोड पर उक्त नाम की कोई दुकान अस्तित्व में ही नहीं है जिससे पूरे मामले में फर्जीवाड़े की आशंका गहरी गई है।

अधिकारी मौन, ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ा: मामले को लेकर जनपद पंचायत स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं। वर्तमान में मझगवां जनपद के प्रभारी सीईओ राहुल पांडे हैं, जिन्हें योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जाना जाता रहा है।



इसके बावजूद इतने गंभीर मामले पर उनकी चुप्पी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

## आरटीई के अंतर्गत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया 4 मई से

मीडिया ऑडिटर, सतना (निप्र)। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रदेश में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया 4 मई से शुरू होगी स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क एवं निवार्य बाल शिक्षा का धिकार धिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के तहत पात्र बच्चों को शासकीय गैर-संशोधन उपरत 30 मार्च 2026 को वक्राश घोषित किए जाने के कारण कुछ भिभावक पुने बच्चों का दस्तावेज सत्यापन निर्धारित समय पर नहीं करा सके।

प्रक्रिया के बाद जिन विद्यालयों में सीटें रिक्त रह गई हैं उन सभी विद्यालयों को उनको रिक्त सीटों सहित द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के लिए पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है। द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में कोई नया पंजीयन नहीं होगा राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजेंदर सिंह ने बताया कि द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में कोई नया पंजीयन नहीं किया जाएगा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए केवल उन्हीं विदकों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने पहले चरण में निवेदन किया था। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2026 को वक्राश निर्धारित होने तथा संशोधन उपरत 30 मार्च 2026 को वक्राश घोषित किए जाने के कारण कुछ भिभावक पुने बच्चों का दस्तावेज सत्यापन निर्धारित समय पर नहीं करा सके।

## सांसद गणेश सिंह के बेटे विकल्प सहित तीन पर 1 साल का प्रतिबंध, अवैध गतिविधियों का आरोप



मीडिया ऑडिटर, सतना (निप्र)। सतना जिला क्रिकेट संघ (डीसीए) में चल रहे विवाद के बीच मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन

(एमपीसीए) के निर्देश पर रीवा डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन (आरडीसीए) ने तदर्थ समिति के तीन सदस्यों को दायित्वों से मुक्त कर दिया है हटाए गए

सदस्यों में सतना सांसद गणेश सिंह के बेटे विकल्प सिंह, राजेश केला और रतन श्रीवास्तव शामिल हैं तीनों पर अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्तता का आरोप है जिसके चलते उन्हें एक साल तक सभागीय क्रिकेट एसोसिएशन की किसी भी जिम्मेदारी से प्रतिबंधित कर दिया गया है आरडीसीए ने तीनों के बिना हस्ताक्षर वाले सामूहिक त्यागपत्र को अमान्य करते हुए यह निष्कासन की कार्रवाई की है वहीं संघ की वार्षिक आम सभा और चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 मई को ही होंगे। बिना हस्ताक्षर और

शर्तों वाले इस्तीफे को किया अमान्य एमपीसीए ने 30 अप्रैल को आरडीसीए को इन तीनों सदस्यों को हटाने के निर्देश जारी किए थे हालांकि कार्रवाई से पहले ही तीनों ने अपना सामूहिक त्यागपत्र भेज दिया था। आरडीसीए के मानसेवी सह सचिव अनुराग सेठी ने एमपीसीए को बताया कि त्यागपत्र पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे और उसमें अन्य सदस्यों पर लगाए गए आरोप भी उचित नहीं थे सेठी ने स्पष्ट किया कि सशर्त त्यागपत्र मान्य नहीं होता है इन्हीं कारणों से त्यागपत्र को अमान्य घोषित कर एमपीसीए के निर्देशानुसार तीनों को

पदमुक्त किया गया विवाद निपटाने बनी थी समिति 3 मई को होंगे चुनाव डीसीए सतना में पिछले कई महीनों से चल रहे विवाद को निपटाने के लिए इस तदर्थ समिति का गठन किया गया था जानकारी के अनुसार इस समिति में सांसद गणेश सिंह के खेमे से कई सदस्य शामिल थे जिनमें उनके बेटे विकल्प सिंह भी प्रमुख थे एमपीसीए ने स्पष्ट किया है कि इस कार्रवाई का चुनाव पर कोई असर नहीं होगा और डीसीए की वार्षिक आम सभा व चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 3 मई को ही आयोजित किए जाएंगे।

## पुलिस ने 20 बिना हेलमेट चालकों पर जुर्माना लगाया

शराब पीकर ड्राइविंग और लापरवाही पर वाहन जब्त, टीम को देख भागा बुलेट ड्राइवर

मीडिया ऑडिटर, मैहर (निप्र)। ताला थाना क्षेत्र में पुलिस ने सड़क सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर विशेष अभियान चलाया पुलिस मुख्यालय के निर्देश और पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह के आदेश पर चलाए गए इस अभियान में नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई बिना हेलमेट चालकों पर चालान अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 20 चालकों को रोका गया इनसे कुल 6 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया पुलिस ने चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए समझाइश भी दी।



शराब पीकर वाहन चलाने पर कार्रवाई: जांच के दौरान एक वाहन चालक को शराब पीकर वाहन चलाते पाया गया। उसके खिलाफ मोटर

कागजात नहीं दिखाए वाहन जब्त: पृच्छाछ के दौरान नवीन शुक्ला वाहन के कागजात नहीं दिखा सका और पुलिस से बहस करने लगा इसके बाद पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत उसकी बाइक जब्त कर ली जब्त वाहन को न्यायालय अमरपाटन में पेश किया जाएगा।